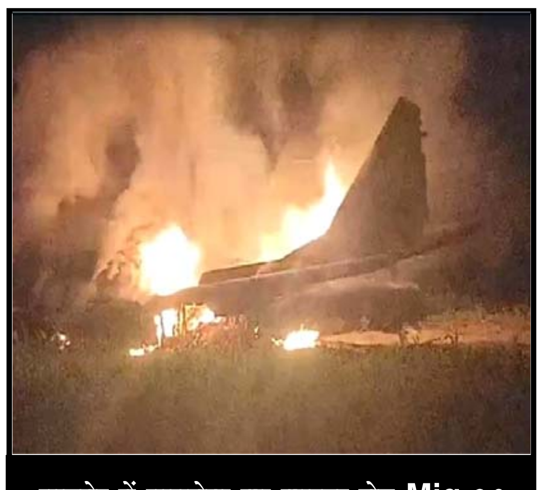

बाडमेर में वायुसेना का फाइटर जेट Mig-29 क्रैश, धूं-धूं कर जला प्लेन, पायलट सुरक्षित

जनहितैषी

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्षः29 अंकः262 दिनांकः03-09-2024 मंगलवार मूल्यः1 रूपया 50 पैसा पृष्ठः4 अहमदाबाद M

'हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया', भाजपा के सदस्यता अभियान के शुभारंभ पर बोले इश मोदी

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट, व्यक्ति दोषी भी....तब भी घर नहीं गिराया जा सकता

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मामलों की सुनवाई सोमवार से शुरू हो गई। जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश कीं। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने बताया कि जो कार्रवाई की गई है, वह नगर-निगम और नगरपालिका के कानून के अनुसार ही की गई है। उन्होंने बताया कि अवैध कब्जे के मामलों में म्युनिसिपल संस्थाओं द्वारा नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई हुई है। जस्टिस विश्वनाथन ने केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने नोटिस, कार्रवाई और अन्य आरोपों पर मोदी सरकार को उत्तर देने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े कर कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाकर कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है,तब भी घर को गिराया नहीं जा सकता। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने इस बात को स्वीकार कर कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वे अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, न कि अपराध के आरोप की वजह से हुई है।

जमीयत उलेमा ए हिन्द ने याचिका दाखिल कर सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में यूपी, मध्यप्रदेश और राजस्थान में हाल में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है।

याचिका पर की गई थी जल्द सुनवाई की हुई थी मांग

वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। याचिका जहांगीरपुरी मामले में वकील फरूख रशीद द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकारें हाशिए पर मौजूद लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाकर उनके घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे पीड़ितों को कानूनी उपाय करने का मौका नहीं मिलता।

एमेनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्यप्रदेश और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से ढहा गया। मध्यप्रदेश में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया, और मुरादाबाद तथा बरेली में भी बुलडोजर से संपत्तियां ढहाई गईं। हाल ही में, राजस्थान के उदयपुर जिले में राशिद खान का घर भी बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिसमें उनके 15 वर्षीय बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से गोदने का आरोप था।

बाडमेर में वायुसेना का फाइटर जेट Mig-29 क्रैश, धूं-धूं कर जला प्लेन, पायलट सुरक्षित

जयपुरः राजस्थान के बाड़मेर में उतरलाई एयरबेस के पास फाइटर प्लेन हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद प्लेन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें प्लेन धू-धूकर जलते हुए देखा जा सकता है। यह हादसा बाड़मेर के कवास के पास हुआ है। वायु सेना का फाइटर मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल एमपीटी रोड के पास आलानियो की ढाणी के पास क्रैश हो गया। हादसे के बाद नागाणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सूचना मिलते ही प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है।

हादसे के दौरान पायलट ने समय रहते पैराशूट की मदद से प्लेन से कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि जब फाइटर प्लेन नियमित रात्रि प्रशिक्षण मिशन पर था। प्लेन में अचानक गंभीर तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते पायलट को आपात स्थिति में विमान से बाहर निकलना पड़ा।

भारतीय वायुसेना ने बयान जारी कर बताया कि बाड़मेर सेक्टर में नियमित रात्रि प्रशिक्षण मिशन के दौरान भारतीय वायुसेना के मिग-29 में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण पायलट को विमान से बाहर निकलना पड़ा। पायलट सुरक्षित है और किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।

प्लेन के क्रैश होते ही आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और वायुसेना अधिकारियों को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर बाड़मेर के जिला कलेक्टर निशांत जैन और एसपी नरेंद्र सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी ली।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 34 उम्मीदवार तय

नई दिल्ली (ईएमएस)। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर सोमवार को मंथन की गयी। जानकारी के अनुसार 34 नामों पर मुहर लग गयी है। वहीं 49 अन्य नामों पर भी चर्चा हुई है। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि बुधवार तक सूची आने की संभावना है।

वैष्णो देवी के रास्ते में लैंडस्लाइड, 2 महिलाओं की मौत

-आंध्र-तेलंगाना में बाढ़ से 19 की जान गई

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश में बारिश का दौर जारी है। मप्र और गुजरात समेत 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। इस बीच जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के नए मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से 3 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 महिलाओं की मौत हो गई। एक लडक़ी का इलाज चल रहा है। अफसरों ने बताया कि दोपहर करीब 2.35 बजे पांची के पास भूस्खलन हुआ। मिट्टी गिरने से मार्ग के ऊपर बना टीन शेड गिर गया। इसकी चपेट में कई लोग आ गए।

उधर,आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ और बारिश के चलते 2 दिनों में आंध्र में 9 और तेलंगाना में 10 लोगों की मौत हुई है। दोनों राज्यों में 140 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। 54 से ज्यादा ट्रेनें डायवर्ट की गई हैं। ह्ष्ठक्रस्न की 26 टीमें तैनात की गई हैं। उफनती नदियों के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। आंध्र प्रदेश में 1998 के बाद ऐसी बाढ़ आई है। 17 हजार लोगों का रेस्क्यू किया गया है। विजयवाड़ा में 2.76 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कुछ इलाकों में 10 फीट तक पानी भरा है। तेलंगाना में सूर्यपेट, भद्राद्री, कोठागुडेम, महबूबाबाद जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। खम्मम के 110 गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। हैदराबाद में आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है।

दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन में फांसी.......ममता के विधेयक को भाजपा का समर्थन

कोलकाता (ईएमएस)। कोलकाता डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले से पूरा देश स्तब्ध है। इस तरह की जघन्य घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग हो रही है। इस बीच ममता सरकार का सोमवार से विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में विधेयक पेश होगा, जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। ममता सरकार के सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक मंगलवार को पेश करने की संभावना है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा विधानसभा में ममता के विधेयक का समर्थन करेगी।

वहीं, बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी बलात्कार के खिलाफ ममता सरकार के विधेयक का समर्थन करेगी। बीजेपी भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि ममता के विधेयक का समर्थन करेगी। हालांकि, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के अंदर भी प्रदर्शन जारी रहेगा।

बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनकी सरकार एंटी-रेप लॉ लाएगी, जिससे रेप के आरोपियों को दस दिन के भीतर मौत की सजा मिल सकेगी। बंगाल विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी ने बताया कि यह बिल विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को पेश होकर उसी दिन चर्चा होकर पारित होगा।

संघ की दो टूक, जाति आधारित जनगणना लोगों के हित में... इसका राजनैतिक इस्तेमाल नहीं हो

पलक्कड़ (ईएमएस)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने कहा कि जाति आधारित जनगणना लोगों के कल्याण के लिए सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनैतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को सिर्फ डेटा के लिए जातिगत जनगणना करनी चाहिए।

संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा, हमारे हिंदू समाज में जाति बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जनगणना हमारी राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए जरुरी है।मामले को बहुत गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। किसी जाति या समुदाय की भलाई के लिए भी सरकार को आंकड़ों की जरूरत होती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन जातिगत जनगणना सिर्फ समाज की भलाई के लिए उपयोग होना चाहिए। राजनैतिक दल इसे चुनावों का पॉलिटिकल टूल न बनाएं।

केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से चल रही तीन दिन की समन्वय बैठक के आखिरी दिन आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आंबेकर ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर, यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) और बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर भी बात की। संघ की बैठक में इन मुद्दों पर की गई चर्चा हुई।

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर

आंबेकर ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) मॉडल पहले से ही जनता के बीच है। उत्तराखंड में यूसीसी को अपनाने से पहले धामी सरकार ने इस पब्लिक डोमेन में रखा था। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और उन्होंने इस पर चर्चा की। मुझे लगता है कि अब यह पब्लिक डोमेन में है। जनता को इसका अनुभव है, फिर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर आंबेकर ने बताया कि बैठक के दौरान कई संगठनों ने बांग्लादेश के हालात पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के बारे में हर कोई चिंतित है। संघ ने मोदी सरकार से हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करने का अनुरोध किया है।

वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधन के मसले पर चर्चा को लेकर आंबेकर ने कहा कि इस मसले पर चर्चा हुई है। यह मुद्दा बहुत बड़ा है। इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा की जानी है। वक्फ को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतें आई हैं। इसकारण इसपर में बड़े स्तर पर चर्चा की जा रही है।

मोदी कैबिनेट ने किसानों को दी 7 सौगात

13966 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी

नई दिल्ली(ईएमएस)। मोदी कैबिनेट ने सोमवार को किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 13,966 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली सात योजनाओं को मंजूरी दी। सरकार ने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसले लिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश भर में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सात महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये उपाय कृषि क्षेत्र को समर्थन देने, सतत विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

इन योजनाओं की दी गई मंजूरी

डिजिटल कृषि मिशनः अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पहला अहम निर्णय है डिजिटल कृषि मिशन। इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमने सफलता हासिल की है, कुल 20,817 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, डिजिटल कृषि मिशन स्थापित किया जाएगा।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञानः दूसरा अहम निर्णय है खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान को बढ़ावा देना। इसके तहत 3979 करोड़ रुपये की लागत से किसानों को जलवायु परिवर्तन के हिसाब से फसल उगाने करने के लिए तैयार किया जाएगा और 2047 तक खाद्य सुरक्षा मिलेगी।

कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को सुदृढ़ बनानाः केंद्र सरकार ने कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए भी 2,291 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा।

सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादनः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है। इसके तहत पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा एवं डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

बागवानी का सतत विकासः केंद्र ने बागवानी पौधों से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बागवानी का सतत विकास करने के उद्देश्य से 860 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र का सुदृढ़ीकरणः केंद्र सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 1,202 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधनः प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए भी 1,115 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का जाति जनगणना पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जाति जनगणना करवाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जाति जनगणना एक नीतिगत मामला है। यह मुद्दा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ता पी प्रसाद नायडू ने सुप्रीम कोर्ट से जाति जनगणना कराने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी। नायडू ने याचिका में कहा था कि केंद्र और उसकी एजेंसियों ने आज तक जनगणना-2021 के लिए गणना नहीं की है। शुरुआत में कोविड-19 महामारी और फिर कई बार स्थगित किया जा चुका है। जनगणना में देरी के कारण डेटा में बड़ा अंतर पैदा हो गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रविशंकर जंडियाला ने कहा कि कई देशों ने जातिगत जनगणना की, लेकिन भारत ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। 1992 के इंद्रा साहनी फैसले में कहा गया है कि यह जनगणना समय-समय पर की जानी चाहिए।

शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों से बात करने सुप्रीम कोर्ट ने की समिति गठित

-कहा- आंदोलन का राजनीतिकरण करने से बचें, समिति के सामने रखें बात

नई दिल्ली,(ईएमएस)। शंभू बॉर्डर पर 6 लेन हाईवे में दोनों ओर एक-एक लेन इमरजेंसी और जन सुविधा के लिए खोली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों की सहमति के बाद ये आदेश जारी किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने राज्य सरकारों की तरफ से सुझाए नामों पर संतुष्टि जताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों के मुद्दों पर विचार करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है। कोर्ट ने कहा कि समिति के सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति और क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन पर सहमति जताई है।

कोर्ट ने कहा कि समिति के विचार के लिए मुद्दों की पहचान करना और उन्हें तैयार करना ज्यादा उपयुक्त होगा। इसके अध्यक्ष ने मुद्दों को तैयार करने के लिए एक हफ्ते में बैठक बुलाई है। समिति के सदस्य सचिव को अंतरिम स्थिति रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में रखने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमएसपी और अन्य मुद्दों हल करने का मसौदा तैयार करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में पांच सदस्यीय पैनल गठित की है।

कोर्ट ने पैनल से शंभू बॉर्डर पर लगाई पक्की बैरिकेडिंग हटाने के लिए किसानों से बातचीत करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि वे अपने आंदोलन का राजनीतिकरण करने से बचें। कोर्ट द्वारा गठित पैनल के साथ अपनी बैठकों में पूरी तरह से मांगें न रखें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की इस कोशिश की हम सराहना करते हैं। पंजाब सरकार ने कहा कि उद्योग, स्कूली बच्चे, दिल्ली एयरपोर्ट आने-जाने वाले सभी परेशान हैं। कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार हाइवे की एक लेन को एंबुलेंस, स्कूल बसें, एमरजेंसी सर्विसेज और आने-जाने वाले लोगों के लिए खोल सकती है, इससे जनजीवन आसान होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले को लंबित रखते हैं, किसानों को भी नहीं लगना चाहिए कि उनको अलग थलग और किनारे कर दिया गया है। हाईवे कोई पार्किंग की जगह नहीं है। हम अखबारों में पढ़ कर आदेश पारित नहीं करना चाहते।

जयपुर में बांध टूटने से कब्रिस्तान में पहुंचा पानी.....लाशें पानी में बहने लगीं

जयपुर (ईएमएस)। जयपुर में बांध टूटने से जलमग्न हुए कब्रिस्तान से लाशें के बहने का मामला सामने आया है। कब्र से कई शव बाहर निकल पानी के तेज बहाव में बहने लगे। यह देख हर कोई दंग रह गया। लेकिन लोगों ने सूझबूझ दिखकर नाले में उतर शवों को आगे बहने से रोका। फिर रस्सी की मदद से कब्र से बाहर आए शवों को निकाला और वापस कब्र में दफन किया।

दरअसल, खोह नागोरियान इलाके में सोमवार सुबह झमाझम बारिश में नूर बांध की दीवार टूटने से बांध का पानी दरगाह के पीछे कब्रिस्तान में घुस गया। इस पानी से कब्रिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो गया और कब्र से 5 शव बाहर आ गए। वहीं, कुछ देर बाद एक-एक कर लाशें पानी के बहाव में बहनें लगीं। जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने वापस कब्र में दफना किया।

इस लेकर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने बताया, पहाड़ियों के बीच में बना बरसों पुराना नूर का बांध अचानक सोमवार सुबह टूटा और उसका पानी बस्ती होकर कब्रिस्तान में पहुंच गया। इस वजह से कुछ जनाजे बहे जिन्हें लोगों ने वापस सुपुर्द-ए-खाक किए। इस लेकर जयपुर कलेक्टर को सूचना देकर मौके पर एसडीआरएफ की टीम भेजी है।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार किया

नई दिल्ली (ईएमएस)। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। घोष को उनके कार्यकाल के दौरान आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष का नाम उनके कार्यकाल के दौरान संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के संबंध में दर्ज किया था।

एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) धारा 420 (धोखाधड़ी) के साथ पठित और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा सात लगाई है, जो एक लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से रिश्वत स्वीकार करने से संबंधित है।

संदीप घोष के अलावा, सीबीआई ने मध्य जोरहाट, बानीपुर, हावड़ा के मेसर्स मा तारा ट्रेडर्स, जेके घोष रोड, बेलगछिया, कोलकाता के मेसर्स ईशान कैफे और मेसर्स खामा लौहा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था।

राज्य स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव देबल कुमार घोष द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर ये प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरजी कर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने याचिका दायर कर संस्थान में कथित वित्तीय कदाचार की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने का अनुरोध किया था।

अली ने उच्च न्यायालय का रुख किया था, क्योंकि इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या संस्थान में कथित भ्रष्टाचार का संबंध महिला डॉक्टर की मौत से जुड़ा है, और क्या पीड़िता को इसकी जानकारी थी एवं इससे मामले के उजागर होने का खतरा था।

अली ने ये भी आरोप लगाया था कि एक साल पहले राज्य सतर्कता आयोग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष घोष के खिलाफ दर्ज कराई गई उनकी शिकायतों का कोई खास नतीजा नहीं निकला और इसके बजाय उन्हें संस्थान से स्थानांतरित कर दिया गया।

चीख-चीख कर बोल रहे सबूत, फिर भी दरिंदा कह रहा- मैं तो बेगुनाह हूं

कोलकाता(ईएमएस)। आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर संग रेप-मर्डर केस में सबूत चीख-चीख कर गवाही दे रहे हैं, मगर आरोपी संजय बार-बार कह रहा कि वह बेगुनाह है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय ने प्रेसिडेंसी जेल में अपनी वकील से पहली बार बातचीत की है। इस दौरान उसने अपनी वकील से कहा है कि वह कोर्ट में खुद को 'बेगुनाह' बताएगा। मीडिया रिपोर्ट्र्स के मुताबिक संजय रॉय के संपर्क में रहने वाले वकीलों के मुताबिक, पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान उससे लगभग 10 सवाल पूछे गए थे। इसमें यह भी पूछा गया था कि मर्डर करने के बाद उसने आगे क्या किया? संजय रॉय ने इसी बात पर बीच में टोकते हुए दावा किया कि उसने मर्डर नहीं किया है और इस तरह का सवाल ही नहीं उठता। उसने कहा कि जब वह रूम में दाखिल हुआ था तो उसने लेडी डॉक्टर को बेहोश पड़ा पाया था।

वकील कविता सरकार से बातचीत में आरोपी संजय रॉय ने यह भी कहा कि उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में भी अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है। उसके वकीलों ने दावा किया कि उससे अलग-अलग तरह के सवाल पूछे गए, जिसमें उसकी पढ़ाई-लिखाई का बैकग्राउंड भी शामिल है। घटना से जुड़े कुछ ही सवाल थे। बता दें कि 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर का शव मिला था। पॉलीग्राफ टेस्ट इस टेस्ट के दौरान और अपनी वकील के साथ बातचीत में आरोपी संजय रॉय ने कहा, 'मुझे फंसाया जा रहा है। मैं उस लेडी डॉक्टर को जानता तक नहीं था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, तो मैंने उसे खून से लथपथ देखा।' संजय का दावा है कि डर और घबराहट की वजह से वह वहां से भाग गया था। सीबीआई अफसरों ने उससे पूछा कि अगर वह दोषी नहीं था तो उसने आरजी कर अस्पताल में पुलिस चौकी को क्यों नहीं बताया? इस पर संजय रॉय ने कहा कि वह घबरा गया था और उसे डर था कि उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होगा।

वहीं, जेल अधिकारियों की मानें तो संजय रॉय को प्रेसिडेंसी जेल के हाई-सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। वह ज्यादातर खुद से ही बातें करता रहता है, जिस तरह से वह बात करता है, उससे डर का अहसास होता है। अधिकारी ने बताया कि उसने अपनी वकील से कड़ी सुरक्षा के बीच लंबी बातचीत की। बता दें कि सीबीआई अधिकारियों ने अब तक कई गवाहों से बात की है। उनका मानना है कि संजय रॉय ध्यान भटकाने और जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मगर संजय रॉय के वकीलों ने दावा किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए उसके बयान की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से की जा सकती है। आरोपी संजय रॉय शरीर पर लगे जख्म और पीड़िता के नाखूनों के नीचे मिला खून और चमड़ी।क्राइम सीन पर मिला एक ब्लूटूथ डिवाइस, जो संजय रॉय के सेलफोन से पेयर हो रहा था। सीसीटीवी फुटेज में वो सेमिनार रूम के पास जाते हुए दिख रहा है। सीबीआई की साइकोलॉजिकल टेस्ट में यह बात सामने आई कि वह सेक्सअल परवर्ट है।

लाल डायरी के राज और फर्जी नियुक्तियां... अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के कारण

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में जांच के तहत सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान और विधायक से जुड़े कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में ओखला इलाके में स्थित अमानतुल्लाह खान के आवास पर तलाशी लेने के बाद धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया।

विधायक के खिलाफ धन शोधन का मामला दो प्राथमिकी से जुड़ा है। वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं के आरोप में खान के खिलाफ एक प्राथमिकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दर्ज कराई थी जबकि दूसरी प्राथमिकी आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने दर्ज थी। सूत्रों ने कहा कि खान (50) ने ईडी के करीब 10 समन को नजर अंदाज किया। आखिरी बार वे अप्रैल में ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए थे। विधायक और उनकी पार्टी ने सबसे पहले सुबह छह बजकर 29 मिनट पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर खबर का खुलासा किया कि ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची है। आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी वीडियो पोस्ट किया।

लाल डायरी ने बढ़ाई मुश्किल!

सितंबर 2022 में घोटाले की जांच के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को एक अहम सबूत मिला था। एसीबी को कौशर इमाम सिद्दिकी उर्फ लड्डन के घर से एक लाल डायरी मिली थी। कौशर को अमानतुल्लाह का करीबी है। एसीबी के मुताबिक, लाल रंग की डायरी में अमानतुल्लाह के कई सारे राज थे और करोड़ों रुपये के लेन-देन का ज्रिक था। एसीबी का शक था कि डायरी में दर्ज करोड़ों रुपये हवाला के जरिए दुबई से भेजे गए थे। ऐसा दावा है कि ये डायरी अमानतुल्लाह के खातों की ही है।

ईडी का आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैरकानूनी तरीके से नियुक्तियां कर अमानतुल्लाह ने काफी पैसा कमाया है। दावा है कि अवैध कमाई का इस्तेमाल अपने करीबियों के जरिए रियल एस्टेट में किया गया।

सोशल मीडिया में ट्रोलिंग वास्तव में नृशंस है - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (ईएमएस)। सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जजों को भी नहीं बख्शा जाता है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग नृशंस है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदार लोगों द्वारा की गई टिप्पणियों को अनदेखा करना सबसे अच्छा है।

दरअसल स्वाति मालीवाल हमला मामले के आरोपी विभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान, कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने ये टिप्पणियां की।

जमानत दिए जाने से पहले मालीवाल की ओर से पेश वकील ने पीठ के समक्ष ये शिकायत की कि घटना के बाद से ही सोशल मीडिया पर पीड़िता को शर्मिंदा करने और ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है।

सेबी चीफ पर कांग्रेस का बड़ा आरोप

एक साथ तीन जगह से सैलरी ले रही थीं माधबी पुरी बुच

नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के चेयरमेन पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में शतरंज का खेल चल रहा है लेकिन खिलाड़ी कौन है, इस पर हम निर्णायक तौर पर पहुंचे नही हैं। अलग-अलग मोहरे हैं। उनमें से एक मोहरे के विषय पर बात करने हम हैं, जिनका नाम है माधबी पुरी बुच।

पवन खेड़ा ने आगे कहा कि माधबी पुरी बुच, सेबी की मेंबर थीं, उसके बाद 2 मार्च 2022 को चेयरपर्सन बनीं। सेबी शेयर मार्केट की रेगुलेटर है और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और गृहमंत्री करते हैं। पवन खेड़ा ने दावा किया कि सेबी चीफ साथ तीन जगहों से सैलरी ले रही थीं। वो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल और सेबी से एक साथ सैलरी ले रही थीं।

माधबी पुरी बुच को इस्तीफा देना चाहिए

पवन खेड़ा ने कहा कि 2017 से 2024 के बीच में करोड़ों की रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक ले रही थीं और ईशॉप पर जो टीडीएस था, वो भी यही बैंक दे रहा था। यह सीधे-सीधे सेबी के सेक्शन-54 का उल्लंघन है। इसलिए अगर माधबी पुरी बुच में थोड़ी भी शर्म होगी तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

जन हितैषी

बिहार में जेडीयू का अंत?

ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी

बिहार की राजनीति में हाल ही में हुई घटनाओं ने जेडीयू के अस्तित्व पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। केसी त्यागी, जेडीयू के कद्दावर नेता और पार्टी के प्रवक्ता थे। उन्हें अचानक राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। इसको केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति के तहत देखा जा रहा है। जिसका उद्देश्य जेडीयू को कमजोर कर खत्म करना और क्षेत्रीय दलों में दहशत पैदा करना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी नड्डा पिछले चुनाव में क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को खत्म होने का दावा कर चुके हैं। जेडीयू के अंदरूनी हालात पर नजर डालने से स्पष्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पहले जैसे सक्रिय और प्रभावी नेता नहीं रहे हैं। उनकी खराब सेहत के कारण पार्टी का नेतृत्व संजय झा और कुछ अन्य नेताओं के हाथों में चला गया है। सत्ता संगठन पर नीतीश की पकड़ कमजोर हो गई है। इस बदलाव ने पार्टी के भीतर और बाहर सत्ता और संगठन के संतुलन को हिला दिया है। केसी त्यागी, ने हाल ही में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना की थी, इसके बाद त्यागी को हटाने के संकेत मिलना शुरू हो गए थे। गृहमंत्री अमित शाह जेडीयू के भीतर असंतोष का फायदा उठाना चाहते हैं। त्यागी ने मुस्लिम समुदाय के प्रति जेडीयू की सकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की थी, जो अब बीजेपी के लिए एक बडी मुसीबत बन रही थी। जेडीयू का पारंपरिक भूमिहार वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगा रही है। अशोक चौधरी के भूमिहारों के खिलाफ दिए बयान से जेडीयू के वोट बैंक को कमजोर कर दिया है। यह स्थिति बीजेपी के लिए जेडीयू की आपदा में एक अवसर है। जेडीयू के समर्थन आधार को भाजपा के पक्ष में करने की तैयारी अमित शाह की रणनीति है। अमित शाह की रणनीति का दूसरा पहलू है, अन्य एनडीए सहयोगियों को भी बिहार और जदयू के माध्यम से संदेश दिया जाए कि एनडीए के भीतर असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है। यही रणनीति चिराग पासवान के मामले में भी देखने को मिल रही है। उन्हें भी तुरंत अनुशासन में लाने की तैयारी कर ली गई है। स्पष्ट है, कि अमित शाह ने जेडीयू को खत्म करने और बिहार में बीजेपी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने की दिशा में कठोर, सटीक और सफल कदम उठाया है। इस रणनीति का उद्देश्य जेडीयू को कमजोर कर खत्म करना है। यह भी सुनिश्चित करना है, कि बाकी सहयोगी दलों में भी बीजेपी के प्रति दहशत के साथ वफादारी बनी रहे। आने वाले समय में, यह देखना होगा, जेडीयू इस चुनौती का सामना किस तरह से करता है। क्या केसी त्यागी जैसे नेता इस राजनीतिक संकट के बीच नए विकल्प की तलाश करते हैं। या पार्टी के अंदर रहते हुये लड़ाई का नया मोर्चा खोलते हैं। केन्द्र की एनडीए सरकार के पास एकमात्र विकल्प बचा है। सहयोगी दल उसके साथ बने रहें। अन्यथा उनके सांसदों को भाजपा में शामिल कराकर उनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाए। एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों द्वारा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के कामकाज में रोड़ा अटकाया जा रहा है। उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काफी नाराज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को सदन में स्पष्ट बहुमत हो। क्षेत्रीय दलों की ब्लैकमेलिंग से बाहर निकलने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री की ओर से ऑपरेशन लोटस शुरु कर दिया गया है। जो भी क्षेत्रीय छत्रप आंख दिखाने की कोशिश करेंगे उनके सांसदों को भाजपा में प्रवेश देकर उस पार्टी को समाप्त करने की रणनीति शुरू हो चुकी है बिहार इसका पहला प्रयोग है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि जब क्षेत्रीय दल ही नहीं रहेगा, रोजाना जो चुनौती मिल रही है वह भी समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार को स्पष्ट बहुमत मिले। इसके लिए अब भाजपा कोई कोर कसर छोड़ने तैयार नहीं है। इस बार भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को निशाने पर लिया है। बिहार की घटना के बाद सहयोगी दलों में भारी दहशत का वातावरण बन गया है। इसकी परिणति कैसी होगी, कहना मुश्किल है।

शर्मनाक है नारी शोषण में पक्षपात

बंगाल की राजधानी महानगर कोलकता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रात की डयूटी अंजाम दे रही एक जूनियर डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को हुआ बलात्कार तथा बलात्कार के बाद उसी जूनियर डॉक्टर की बेरहमी से की गयी हत्या का मामला इन दिनों देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे के रूप में मीडिया में छाया हुआ है। इस बलात्कार व हत्या के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जांच भी शुरू हो चुकी है। उस समय यह मामला और भी हाई प्रोफ़ाइल हो गया जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गत दिनों पीटीआई को दिए अपने साक्षात्कार में इसी कांड के सम्बन्ध में यह कह दिया कि मैं बहुत निराश और भयभीत हूं। बेटियों के ख़िलाफ़ अपराध बर्दाश्त नहीं। राष्ट्रपति ने कहा, बस अब बहुत हुआ। इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रपति महोदया ने इसी विषय पर और भी बहुत सी बातें कर हमारे समाज की बेटियों और बहनों के साथ हो रहे इस तरह के अत्याचारों पर गहन चिंता ज़ाहिर की। उन्होंने पूरे समाज का आवाह्न किया कि सब मिलकर इस विकृति का सामना करें ताकि इसे शुरुआत में ही ख़त्म किया जा सके।

राष्ट्रपति महोदया द्वारा कोलकता रेप व हत्याकांड का ज़िक्र अपने इंटरव्यू में करने के बाद यह चर्चा भी सुनाई देने लगी है कि क्या बंगाल में इसी शर्मनाक काण्ड की आड़ में निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर वहां राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है ? इससे पहले भी बंगाल में संदेशखाली की कुछ महिलाओं ने कथित तौर पर यह आरोप लगाया था कि मुख्य मंत्री ममता बनर्जी के क़रीबी तृणमूल नेताओं द्वारा प्रशासन का डर दिखाते हुए उन लोगों पर अत्याचार किया गया। उनकी ज़मीन छीन कर उस पर क़ब्ज़ा कर लिया गया। विरोध करने पर हमले किये गये। ज़मीन लीज़ पर लेकर पैसे भी नहीं दिये गये, पैसे देने का वादा करने के बावजूद पैसे मार लिये गये और शारीरिक शोषण भी किया गया,आदि आदि। हालांकि इसी मामले में तृणमूल नेताओं पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली तीन महिलाओं में से दो ने केस वापस भी ले लिया था। तृणमूल कांग्रेस ने 'स्टिंग ऑपरेशन' के एक वीडियो में दावा किया था कि बीजेपी के स्थानीय नेता ने कई महिलाओं से सादे काग़ज़ पर दस्तख़त करवाए थे और बाद में तृणमूल नेताओं के विरुद्ध बलात्कार व यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाने में इन काग़ज़ों का प्रयोग किया गया था। इस साज़िश के पर्दाफ़ाश होने के बाद यह मामला जितनी तेज़ी से मीडिया में उछाला गया था उतनी ही तेज़ी से यह दबा भी दिया गया। संदेशखाली की घटना के बाद भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की चर्चा सुनाई देने लगी थी।

बलात्कार हत्या जैसे घृणित अपराध निश्चित रूप से कहीं भी हों इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिये। शासन व प्रशासन व विधायिका को मिलकर ऐसे उपाय ढूंढने चाहिये जिससे अपराधियों के हौसले पस्त हों और वे ऐसे अपराधों की जुरअत ही न कर सकें। साथ ही समाज को अपने बच्चों को भी शिक्षित करना चाहिये। परन्तु अफ़सोस तो इस बात का है कि हमारे देश में बलात्कार व हत्या जैसे घिनौने अपराध को लेकर भी राजनीति की हांडी चढ़ा दी जाती है। राज्य में सरकार किस दल की है,यह देखकर बलात्कार का विरोध किया जाता है। और इससे भी शर्मनाक यह कि बलात्कार पीड़िता का धर्म व उसकी जाति देखकर भी मामले का विरोध व समर्थन निर्धारित किया जाता है। आरोपी /अपराधी के रसूख़ के अनुसार भी उसके साथ बर्ताव किया जाता है। यहाँ तक कि यदि बलात्कार व हत्या का अपराधी बड़ी संख्या में अपने अनुयायी रखता है तो उस पर तो शासन की विशेष कृपा बरसते देखी जा सकती है। ख़ासकर चुनावी बेला में तो ऐसे सफ़ेदपोश अपराधियों को विशेष पेरोल तक दे दी जाती है।

याद कीजिये गुजरात में 2002 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान बिलक़ीस बानो व उसकी मां के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था तथा उसी समय उनके सामने उन्हीं के परिवार के सात सदस्यों की हत्या भी कर दी गयी थी। इस लोमहर्षक जुर्म में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय द्वारा 11 अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गयी थी। परन्तु मई 2022 में गुजरात सरकार ने अच्छे चरित्र के आधार पर दोषियों की सज़ा में छूट देते हुये स्वतंत्रता दिवस के दिन इनको रिहा कर दिया था। एक तरफ़ तो भारत सहित पूरे विश्व में गुजरात सरकार के इस क़दम की घोर आलोचना हुई थी। तो दूसरी तरफ़ इन हत्यारे बलात्कारियों को मंच पर सुशोभित किया जाने लगा था। इन्हें फूल माला पहनाकर इन हत्यारे बलात्कारियों का स्वागत किया जा रहा था। इसी आलोचना के दौरान एक विश्व हिन्दू परिषद् के पक्षकार विद्वान लेखक ने इन हत्यारे बलात्कारियों का पक्ष लेते हुये अपने आलेख को इस आशय के शीर्षक से सजाया था कि -आख़िर हिन्दुओं को भी तो जीने का अधिकार है ? यह तो भला हो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयन का जिन्होंने इस मामले में संज्ञान लेते हुये - कहा कि मई 2022 में गुजरात सरकार ने दोषियों की सज़ा में छूट देकर तथ्यों की उपेक्षा की थी। और इसी टिप्पणी के साथ उन्होंने सभी दोषियों को दो हफ़्ते के भीतर जेल प्रशासन के पास हाज़िर होने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय यह भी कहा था कि गुजरात सरकार के पास सज़ा में छूट देने और इस बारे में कोई फ़ैसला लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह अपराधी पुनः जेल जा सके थे और इन हत्यारे बलात्कारियों के हमदर्दों को अपनी मुंह की खानी पड़ी थी।

इसी तरह जनवरी 2018 के कठुआ,जम्मू के 8 वर्ष की मासूम असिफ़ा बानो के सामूहिक बलात्कार व उसकी हत्या के समय भी बलात्कार समर्थक इन बेशर्मों चेहरा बेनक़ाब हुआ था। इस घृणित अपराध का साज़िशकर्ता एक रिटायर्ड राजस्व अधिकारी था जोकि उस समय एक स्थानीय मंदिर का पुजारी भी था जहाँ कई दिनों तक उस बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता रहा। इस घटना को भी धार्मिक रंग देते हुये स्वयं को हिन्दू हितैषी कहने वाले लोग बलात्कारियों के पक्ष में केवल खड़े ही नहीं हुये बल्कि उनके समर्थन में जुलूस निकाले, प्रदर्शन किये और हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। पूरा विश्व उस घिनौनी ख़बर से हिल गया था जबकि सैकड़ों की भीड़ ने वर्ग विशेष की लड़कियों से नग्न परेड कराई और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किये गये। ऐसे अनेक घटनायें मणिपुर में घटीं। उत्तरांचाल,मणिपुर राजस्थान,मध्य प्रदेश कहाँ नहीं हो रहा है बलात्कार ? परन्तु क्या मीडिया तो क्या सरकारी तंत्र व विशेष विचारधारा के लोग इन सबको केवल ग़ैर भाजपा शासित राज्यों में ही ऐसे अपराध नज़र आते हैं ? यदि बलात्कारियों व हत्यारों को दलगत अथवा धर्म व जाति के चश्मे से देखा जाने लगा यानी नारी शोषण में भी पक्षपात किया जाने लगा फिर हमारे देश के लिये इससे निंदनीय व शर्मनाक और क्या हो सकता है ? (लेखक – तनवीर जाफ़री / ईएमएस)

वैज्ञानिक युग की देन है सामाजिक इतिहास

इतिहास के क्षेत्र का वर्गीकरण वैज्ञानिक युग की देन है। सामाजिक इतिहास, इतिहास की एक सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। कोम्ते के अनुसार इतिहास सामाजिक भौतिक शास्त्र है। इसके अंतर्गत् मानवीय व्यवहार के सामान्य नियमों का अध्ययन किया जाता है। टायन्वी का कहना है कि इतिहास का निर्माण सामाजिक अणु तत्वों से हुआ है। इतिहास का विकास व्यक्तियों तथा राष्ट्रों से नहीं, बल्कि विभिन्न युगीन समाजों से हुआ है।सामाजिक इतिहास के अभाव में इतिहास बंजर तथा अवर्णनीय है। आदिकाल से आधुनिक युग तक इतिहास क्षेत्र का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील रहा है। इसके विकसित स्वरूप का एकमात्र आधार विभिन्न युगों के सामाजिक मूल्य तथा उसकी सामाजिक आवश्यकताएं रही है। समाज का क्षेत्र काफी विस्तृत है और समाज के सभी क्षेत्र के विषयों का इतिहासकार उचित विवरण एक साथ नहीं दे सकता है। इसलिए आधुनिक इतिहासकारों ने इतिहास क्षेत्र का वर्गीकरण किया है। आधुनिक इतिहासकारों के वर्ग में प्रत्येक इतिहासकार विशिष्ठ विषय का विशेष ज्ञान रखता है और अपने ज्ञान से संबंधित सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य विषयों की विवेचना करता है। इसके अंतर्गत् अनेक छोटी-से-छोटी शाखाओं पर शोध करके इतिहासकारों ने विशिष्ठ ज्ञान को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार इतिहासकारों ने अतीत कालिक घटनाओं के आधार पर ामाजिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इतिहास क्षेत्र का वर्गीकरण किया है।सामाजिक इतिहास को महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय ट्रेनेलियन को जाता है। उन्होंने सामाजिक इतिहास के अंतर्गत् अतीत में लोगों के दैनिक जीवन, परिवार का स्वरूप, विभिन्न वर्गो का पारस्परिक आर्थिक संबंध, ग्रहस्थ जीवन, श्रमिकों की दशा, प्रकृति के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, सांस्कृतिक जीवन तथा सामान्य परिस्थितियों से उत्पन्न धर्म, साहित्य, संगीत, वास्तुकला, शिक्षा तथा साहित्य है। रेनिलर ने कहा है कि- सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास की पृष्ठभूमि तथा राजनीतिक इतिहास की कटौती हैं। ट्रेवेलियन ने भी कहा है कि सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास माध्यम तथा राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय है। आदिकालीन परिस्थितियों को जानना अत्यधिक आवष्यक है। मनुश्य अपने जीवन में बहुत कुछ विगत से जानता व सीखता है। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वह सामाजिक इतिहास का क्षेत्र है। वह भारतीय संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित था। उत्सव, मेले, परिधान, आहार विवाह, मनोरंजन, आदि, समाज शास्त्र का क्षेत्र है। समाज शास्त्र का विकास सामाजिक इतिहास के परिवेश में ही हुआ है। सामाजिक विकास तथा परिवर्तन की प्रतियों का अध्ययन समाज शास्त्र के माध्यम से ही प्रारंभ हुआ। इसलिए सामाजिक इतिहास की विशेषता इसलिए भी है कि एक समाज की जितनी आवश्यकताएं, समस्याएं, विकास, उत्थन, पतन, भौगोलिक परिवेश, मानवीय कार्य एवं उनकी उपलब्धियां होती हैं, उन सबका संबंध समाज से होने के कारण सामाजिक इतिहास में इनका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक इतिहास में निजी समाज से संबंधित भौगोलिक दशा, वातावरण, आर्थिक व्यवस्था, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, संवैधानिक, कानून, न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था आदि का विवरण आवश्यक ही जाता है।सभी इतिहासकारों का उद्देश्य सामाजिक मूल्यों तथा आवश्यकता के अनुसार इतिहास का प्रस्तुतिकरण करना होता है। हेरोडोढस ने मकाकाण्य युग में इतिहास की सामाजिक आवश्यकता कहानी मात्र समझा था। लेकिन 20वीं सदी में अधिकांश इतिहासकारों का ध्यान सामाजिक इतिहास की विशिष्ठता की ओर गया। सामाजिक समस्याओं के प्रति चेतना ने इतिहास के क्षेत्र में रूचि पैदा की। सामाजिक इतिहास की अपनी समस्याएं हैं। इसका अध्ययन रोचक है। परन्तु इसकी निरंतरता, भेदगति तथा परिवर्तन का अध्ययन अत्यंत जटिल है। राजनीतिक परिवर्तन को जीवन में सहज ही देखा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन के कारण राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। एक राज्य, नया संसद, राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए परिवर्तन का प्रभाव सामाजिक जीवन पर नहीं पड़ता है। भारतीय इतिहास में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण अनेक राजवंशों का उत्थन-पतन हुआ है। राजपूतों के पतन के बाद तुर्की, सुल्तानों, मुगलों तथा अंग्रेजों का शासन हुआ। परन्तु इन परिवर्तनों के सामाजिक परिवर्तन को प्रायः प्रभावित नहीं किया है। परिणामस्वरूप भारतीय समाज का मूल स्वरूप आज भी वही है, जैसा गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी के समय था। आदिकाल में समाजिकए भक्ति, वीर तथा ऐतिहासिक, धार्मिक आदि, कई प्रवृत्तियाँ समाज व इतिहास से संबंधित हैं। भक्ति आंदोलन के समाज सुधारक रामानंद, कबीर, नानक तथा चैतन्य ने समाज सुधारने के लिए अथक प्रयास किया। राजाराम मोहनराय, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू ने भी समाज सुधार का प्रयास किया। सांसद तथा विधान सभाओं ने अनेक नियम पारित किए। इतने प्रयास के बावजूद सामाजिक स्वरूप में किसी प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि सामाजिक परिवर्तन हुआ भी है तो वह भूमिगत और अगोचर रही है, उसका सूक्ष्म निरूपण कठिन प्रतीत होता है। समाज शास्त्रियों ने इस परिवर्तन की गति का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। सामाजिक इतिहास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। समाज का दर्पण है सामाजिक इतिहास। जो कुछ समाज में घटित होता है उसकी भावात्मक स्थिति और गतिषील चेतना की अभिव्यक्ति है।इसी तरह राजनीतिक परिवर्तन के कारण अनेक सामाजिक प्रक्रिया का दौर भी चलता है। जैसे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए स्वदेशी आंदोलन ने यहाँ भारतीय समाज में स्वदेशी कपड़ों के उपयोग के प्रति जागरूकता पैदा की। वहीं असहयोग आंदोलन ने समाज में होने वाले अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का आधार दिया। साथ ही शराब बंदी, छुआछूत की भावना में कमी, स्त्रियों की भूमिका के प्रति सोच में परिवर्तन आया। सामाजिक इतिहास में समाज से संबंधित इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक इतिहास सम्पूर्ण इतिहास क्षेत्र की रीढ़ है। इतिहास में जितने भी अन्य क्षेत्र हैं, उन सबका संबंध समाज से ही है। चाहे वे राजनीतिक हों, आर्थिक हों, संवैधानिक हों या सांस्कृतिक, समाज में इन सभी का सामाजिक इतिहास नहीं होगा, तो समाज के विभिन्न अंगों में होने वाले परिवर्तनों, उपलब्धियों, कार्यों, घटनाओं एवं समाज की उपयोगिताएं समस्याओं से समाज की उपयोगिताएं, समस्याओं से समाज में रहने वाले लोग परिचित नहीं हो पाएंगे। सामाजिक इतिहास के माध्यम से मानव अपने प्राचीन युग की खूबियों, उपलब्धियों, कमियों को संजोकर रखता है। अपने पूर्वजों के कार्यकलापों, उनके सामाजिक जीवनशैली, समाज में होने वाले सांस्कृतिक क्रियाकलापों, उनके क्रमिक विकास की जानकारी भी हमें सामाजिक इतिहास से मिलती है। यदि सामाजिक इतिहास नहीं होगा तो राजनीतिक तथा आर्थिक इतिहास का महत्व उसके अभाव में कम हो जाएगा, क्योंकि समाज में ही मनुष्य रहते हैं और अपने जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष की प्रक्रिया में ही अनेक आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन होते हैं। अपने जीवित रहने के संघर्ष की प्रक्रिया के कारण ही मनुष्य ने आग और अन्न की खोज की और समाज असभ्यता से सभ्यता की सीमा में पहुँच सका।इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक इतिहास, इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है, साथ ही इसमें बहुत अंशों में समाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित बातों का अध्ययन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि, ''सामाजिक इतिहास के अभाव में इतिहास बंजर तथा अवर्णनीय है।'' क्योंकि समाज में ही इतिहास का निर्माण होता है। यदि समाज ही नहीं होगा तो उनकी गौरवगाथा के बखान, वर्णन करने के लिए सामाजिक इतिहास ही नहीं होगा, तो इतिहास ही अरूचिकर, रोमांचविहीन और नीरस हो जाएगा। इसलिए इतिहास के लिए सामाजिक इतिहास बहुत जरूरी है। (लेखिका- डॉ अंकिता मिश्रा / ईएमएस)

सत्ता का गुलाम आखिर कौन?

बहुत दिनों बाद एक ढंग का विषय मिला है । इसके लिए धन्यवाद उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। 52 साल के योगी जी ने विमर्श के लिए ये विषय हालांकि हवा में उछाला है ,लेकिन ये जरूरी विषय है कि -आखिर सत्ता का गुलाम है कौन ? योगी ने आदित्यनाथ ने चंदौली में एक कार्यक्रम में कहा कि कोई योगी या संत सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा, संत समाज को एकजुट करते हैं। पूरे समाज को एकसाथ जोड़कर संत चलता है।

योगी ने यह बातें अघोराचार्य बाबा कीनाराम की जन्मस्थली पर आयोजित 425 अवतरण समारोह को संबोधित करते हुए कही। योगी से बहुत साल पहले संत कुम्भनदास ने यही बात कही थी। उन्होंने कहा था -

संतन को कहा सीकरी सों काम?
आवत जात पनहियाँ टूटी, बिसरि गयो हरि नाम॥
जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम॥
कुभंनदास लाल गिरिधर बिनु, और सबै बेकाम॥

कुम्भनदास किसान थे,संत थे और उस समय के संत थे , जब संत होना कठिन काम था। लेकिन कुम्भनदास के पांच सौ साल बाद संत होना कठिन काम नहीं रह गया। अब संत सींकरी आने-जाने के अभ्यस्त हो चुके हैं। जो सींकरी नहीं जाते उन्हें जेल जाना पड़ता है ,जो सींकरी जाते हैं उन्हें फलरो के तहत जब चाहे तब जमानत मिल जाती है भले ही वे हत्या और बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे हों। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या आज के संत और योगी सत्ता के गुलाम हैं या नहीं ?

योगी जी यानि बाबा आदित्यनाथ 26 साल से राजनीति में हैं और सत्ता में रहते हुए भी उन्हें 9 साल हो चुके हैं और वे कहते हैं ,गर्व से कहते हैं कि- योगी और संत सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। क्या आप योगी आदित्यनाथ के इस दावे पर यकीन कर सकते हैं ? योगी जी को जिन परिस्थितियों में सत्ता के मयूरपंखी सिंहासन पर बैठाया गया था ,वो आपको याद होगा और जिस तरह से उनके सिंघासन को पिछले पांच साल से अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है वो भी आप सबसे छिपा नहीं है। यदि योगी जी सत्ता के गुलाम नहीं है तो बादशाह की जीप के पीछे-पीछे उपने डनंगे पांव .क्यों दौड़ लगा रहे हैं ? क्या वे सत्ता को ठोकर मारकर गोरखपुर वापस नहीं लौट सकते ?

संतो-महंतों और योगियों को सत्ता में लाने का,सत्ता का गुलाम बनाने का एकमेव श्रेय यदि किसी राजनीतक दल को है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने देश में राम राज की स्थापना करने के मकसद से संतों-महंतों को सत्ता का गुलाम बनाने की कोशिश की । कांग्रेस के जमाने में भी संत-महंत सत्ता के साथ चस्पा रहते थे, किन्तु उनकी सत्ता में सीधी भागीदारी नहीं थी। भाजपा ने साध्वी उमा भारती को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया ,केंद्र में मंत्री बनाया। अनेक साध्वियों को विधानसभाओं और लोकसभाओं में भेजा । मंत्रिमंडलों में शामिल किया। इनकी फेहरिस्त बहुत लम्बी है। लेकिन एक योगी आदित्यनाथ को छोड़ सभी को भाजपा ने दूध में पड़ी मख्खी की तरह निकाल भी दिया। अब कोई गौसेवा कर रहा है तो कोई अदालतों के चक्कर काट रहा है।

योगी आदित्यनाथ के इस कथन से कि संत-महंत सत्ता के गुलाम नहीं होते, मै पूरा इत्तफाक रखता हूँ ,लेकिन उनकी ये बात मोदी युग में सही साबित नहीं होती । वो दौर दूसरा ही था ,जब संत-महंत और योगी सत्ता को लतियाते हुए आगे बढ़ जाते थे। अब तो साधू-संत,महंत और योगी सत्ता के न सिर्फ गुलाम हैं बल्कि सत्ता के चरण-चुंबन में सबसे आगे हैं। जिन्हें सत्ता चाहिए वे दल नहीं देखते,केवल सत्ता देखते है। उत्तर प्रदेश में एक संत हैं प्रमोद कृष्णा। कांग्रसी संत थे ,लेकिन अब भाजपाई संत हैं। हमारे चार शंकराचार्य इसके अपवाद हैं ,लेकिन वे सत्ता के गुलाम न होते हुए भी सत्तानुरागी तो हैं ही। सबकी अपनी-अपनी पसंद है । किसी को कांग्रेस की सत्ता अच्छी लगती है, तो किसी को भाजपा की सत्ता। सत्ता विमुख होकर कोई धर्माचरण नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री कि शपथ ग्रहण समरोह बिना संतों-महंतों कि पूरे ही नहीं होते ।

मेरी दृढ मान्यता है कि देश के साधु,संत,महंत और योगी जिस दिन सत्ता की गुलामी करना छोड़ देंगे उस दिन से सत्ता जनता को धर्म की अफीम चटाना बंद कर देगी ,लेकिन दुर्भाग्य ये हो नहीं रहा । हो नहीं सकता। सत्ता होने नहीं दे रही संतों को गुलामी से मुक्त। इसका आगाज , योगी आदित्यनाथ से ही हो सकता है , किन्तु वे भी अब सत्ता से ऐसे चिपके हैं जैसे कोई फेविकोल का जोड़ हो। आदित्यनाथ रो सकते हैं ,अपमानित हो सकते हैं लेकिन सत्ता का त्याग नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने 9 साल में देख लिया हैकि जगत मिथ्या है और सत्ता ही परम सत्य है। सत्ता का त्याग करना आसान काम नहीं है। सत्ता से या तो राजनीतिक दलों का हाईकमान लतियाता है या फिर जनता। उत्तर प्रदेश में जनता पिछले आम चुनाव में अपने रुख का संकेत दे चुकी है । खुद योगीजी के उत्तर प्रदेश में भाजपा औंधे मुंह गिरी है। लेकिन योगी जी जहाँ थे,वहीं हैं।

योगी जी के दावे को सुनकर हंसी आती है कि संत,मेहनत या योगी सत्ता के गुलाम नहीं होते। योगी जी कहते हैं कि- सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है। योगी कहते हैं कि जब किसी को सिद्धि या कुछ भी प्राप्त होता है, तो वह उसके मद में किसी को कुछ नहीं समझता है। लेकिन योगी सभी को एकजुट कर आगे बढ़ता है। बात सही भी है । योगी जी उत्तरप्रदेश में पार्टी हाईकमान कि कहने पर केर-बेर कि संग मिलकर सरकार चला रहे हैं। योगी जी जैसी दक्षता उमा भारती में नहीं थी। 65 साल की उमा भारती पांच बार सांसद रहने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मात्र 9 माह रह पायीं थी । उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी कि हाईकमान को लतियाया था ,लेकिन योगी आदित्यनाथ आज तक उमा भारती जैसा साहस नहीं जुटा पाए,फलस्वरूप उनकी कुगति हो रही है। वे पूरे संत-महंत और योगी समाज का अपमान करा रहे हैं। वे अपने पूर्वज कुम्भनदास का अपमान करा रहे हैं। योगी जी से सींकरी छूटती ही नहीं।

बहरहाल ये कलिकाल है। कलिकाल में भी,मोदीकाल है। इस काल में संत,महंत ,योगी सबके सब सत्ता कि गुलाम हैं ,जो नहीं हैं वे भी होना चाहते हैं। जो नहीं हो पा रहे हैं वे सत्ता को ,मोदी को कोसते रहते हैं। जो नहीं कोस रहे वे उममीद पाले हुए हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें भी सत्ता का सुख मिल सकता है। उम्मीद बड़ी चीज होती है। भक्ति से भी बड़ी। जो सत्ता का गुलाम नहीं है, वो योगी नहीं है । वो संत नहीं है,वो महंत नहीं है। सत्ता सभी को अपना गुलाम बनाना चाहती है। संत,महंत,योगी, ध ा ा ` ग ा ा ˆ , मीडिया,कार्यपालिका,न्यायपालिका सब सत्ता कि निशाने पर हमेशा से रहे हैं और आज भी है। बल्कि आज पहले से ज्यादा हैं । आप इस बारे में जो सोचते हों वो प्रकट भी करें ,तभी ये विमर्श पूरा हो सकता है। (लेखक-राकेश अचल/ईएमएस)

शब्द पहेली - 8117

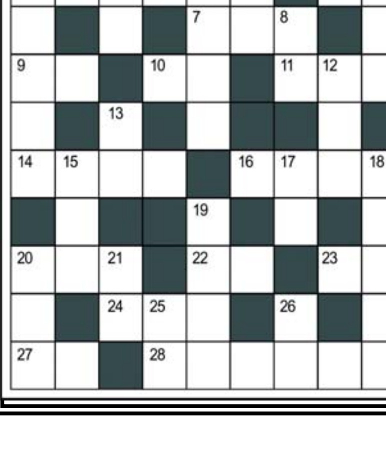

बाएँ से दाएँ

1. परिचय, जानना-2,4
5. वायु रोग-2
7. उत्साह, जिज्ञासा
9. कांटा, शूल
10. पिता, साधू-2
11. योद्धा जाति, राजपूत-3
14. थकान-4
16. मिसाल के तौर पर-4
20. ध्वजा, पताका-3
22. सीमा, बार्डर-2
23. बुरी आदत-2
24. समस्या, मुद्दा-3
27. जोर, दम, ताकत-2
28. दिखावटीपन, आडंबर, -3,3

ऊपर से नीचे

1. सीतापति, रामचंद्र-5
2. लम्हा, क्षण-2
3. धोखेबाज, दगाबाज-4
4. नलका, टोंटी-2
6. पुत्र, लड़का-3
8. कमरा, रूम-2
12. तीनों काल-3
13. पार्थिव शरीर, लाश-2
15. कजरा, अंजन-3
17. सच्चाई, सच-2
18. सेंधमार-5
19. पुचकारना, हाथ फेरना-4
20. धोखा, दगा-3
21. जरा, थोड़ा-2
25. सभी, संपूर्ण-2
26. राजेश खन्ना व मुमताज की बेहतरीन फिल्म-2

शब्द पहेली -8116 का हल

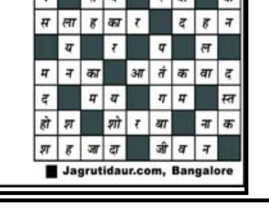

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

पेरिस पैरालिंपिक में नितेश कुमार ने बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण जीता

योगेश ने डिस्कस थ्रो में रजत जीता

पेरिस (ईएमएस)। भारत के नितेश कुमार ने पेरिस पैरालिंपिक खेलों की बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ ही भारत ने दूसरा स्वर्ण जीता। अब भारत के पदकों की कुल संख्या 9 हो गयी है। नितेश ने बैडमिंटन पुरुष एकल के एसएल 3 वर्ग में ये स्वर्ण पदक जीता। नितेश ने ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराया। नितेश ने पहला गेम 21-14 से जीता, दूसरा गेम बेथेल 18-21 से जीत गए। तीसरे गेम में मुकाबला 21-21 की बराबरी पर पहुंच गया, यहां नितेश ने लगातार 2 अंक हासिल कर स्वर्ण जीत लिया।

वहीं डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने भी आज रजत पदक जीता। भारत को पैरालिंपिक खेलों में निशानेबाज अवनि लेखरा ने पहला स्वर्ण जिताया था।

पैरालिंपिक में भारत ने अब तक 2 स्वर्ण , 3 रजत और 4 कांस्य जीते हैं। वहीं पैरा बैडमिंटन मिक्स्ड एसएच-6 इवेंट में भारत की नित्या श्री सिवान और शिवराजन सोलाईमलाई मैच हार गए। उन्हें इंडोनेशिया के सुभान और मर्लिना ने 21-17, 21-12 से हरा दिया।

श्रीलंका पर जीत से इंग्लैंड को मिले 81 डब्यूटीसी अंक

लंदन (ईएमएस)। इंग्लैंड को लॉर्ड्स में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में मिली 190 रनों की जीत के साथ ही 81 डब्यूटीसी अंक मिले हैं। इस प्रकार उनका डब्लयूटीसी अंक प्रतिशत 45 पहुंच गया है पर वह अभी भी अपने पहले वाले स्थान पर ही है। इस प्रकार इंग्लैंड की टीम भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर श्रीलंका की टीम के अंक प्रतिशत हार के कारण 40 से गिराकर 33.33 तक पहुंच गये हैं। इस प्रकार श्रीलंकाई टीम अब दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बाद सातवें स्थान पर फिसल गयी है।

इस मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले गस एटकिंसन अब भारत के रवींद्र जडेजा के बाद एक ही टेस्ट में पांच विकेट लेने और शतक बनाने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। एटकिंसन टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले इंग्लैंड के तीसरे पुरुष खिलाड़ी हैं। इससे पहले इयान बॉथम ने पांच बार जबकि टोनी ग्रेग ने एक बार पांच विकेट लिए थे। आईसीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एटकिंसन 1984 के बाद से ऐसा करने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

फाफ डू प्लेसिस की टीम सेंट लूसिया किंग्स ने दर्ज की जीत

जमैका (ईएमएस)। फाफ डू प्लेसिस की टीम सेंट लूसिया किंग्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की हे। इस मैच में सेंट लूसिया किंग्स ने एक समय पर 24 रन पर 4 विकेट खो दिये थे। इसके बाद भी उसने 202 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। इस मैच में कुल 58 बाउंड्री लगी और 403 रन बने। वहीं सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की ओर से इविन लुईस ने शतकीय पारी खेली पर वह अपने टीम को हार से नहीं बचा पाये।

डू प्लेसिस की टीम सेंट लूसिया किंग्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत तेजी से की। सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ओपनर इविन लुईस की तेज शतकीय पारी और काइल मायर्स के 92 रन की बदौलत 3 विकेट पर 201 रन बनाए। लुईस ने 54 गेंद पर 7 चौके और 9 छक्के लगाते हुए 100 रन बनाए जबकि 62 गेंद पर 6 चौके और 7 छक्के मार कर काइल ने 92 रन बनाए।

वहीं 201 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट लूसिया किंग्स की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने केव 24 रन के स्कोर पर चार विकेट खो दिये हालांकि इसके बाद भी टीम 17.2 ओवर में 5 विकेट से जीत गयी। भानुका राजपक्षे ने 35 गेंद पर 6 चौके और 4 छक्के लगाकर नाबाद 68 रन बनाये। वहीं टिम सेईफर्ट ने 64 रन बनाए।

भारत के निषाद ने पैरालंपिक खेलों में रजत जीता

पेरिस (ईएमएस)। भारत के पैरा एथलीट निषाद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीता है। निषाद ने पुरुषों की टी47 ऊंची कूद स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल करते हुए ये पदक जीता है। इसी के साथ ही पेरिस पैरालंपिक में एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य के साथ भारत के कुल पदकों की तादद सात हो गयी।

रविवार देर रात हुए मुकाबले में निषाद ने पुरुषों की टी47 ऊंची कूद स्पर्धा में अपनी 2.04 मीटर की छलांग के साथ ही पेरिस पैरालंपिक खेलों का रजत पदक अपने नाम किया। वहीं अमेरिका के रॉडरिक टाउनसेंड-रॉबट्र्स ने 2.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। जबकि रूस के जॉर्जी मार्गिएव ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं भारत की ही प्रीती पाल ने पैरा ओलंपिक्स में दूसरा कांस्य पदक जीता है। प्रीति ने पैरालंपिक की अलग-अलग स्पर्धाओं में ये पदक जीते हैं। प्रीती ने दो सौ मीटर टी-35 इवेंट में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने दो सौ मीटर टी-35 इवेंट में भी एक कांस्य जीता था।

प्रीती ने पैरा ओलंपिक्स में दूसरा कांस्य पदक जीता

मुजफ्फरनगर (ईएमएस)। भारत की प्रीती पाल ने पैरा ओलंपिक्स में दूसरा कांस्य पदक जीता है। प्रीति ने पैरालंपिक की अलग-अलग स्पर्धाओं में ये पदक जीते हैं। प्रीती ने दो सौ मीटर टी-35 इवेंट में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने दो सौ मीटर टी-35 इवेंट में भी एक कांस्य जीता था। इसके बाद से ही उनके उत्तर प्रदेश के मेरठ के हाशमपुर में जश्न का माहौल है। प्रीति पाल सेरेब्रल पाल्सी बीमारी से पीड़ित हैं।

जैसे ही प्रीति के पदक की बाज घर पहुंची। उनके परिजन ख़ुशी से झूम उठे। दादा ऋषिपाल और बहन नेहा ने मिठाई बांटी। दादा के अनुसार प्रीति ने बाधाओं को पार करते हुए ये जीत दर्ज की है। प्रीति जन्म के बाद से ही एक दशक तक बेड पर ही रही पर हार न मानने के जज्बे से वह यहां तक पहुंची है।

प्रीति को 17 साल की उम्र में ही पैरालंपिक खेलों के बारे में पता चला था। इसके बाद सीनियर खिलाड़ियों की मदद से वो आगे बढ़ती रहीं। अब खेलों में दूसरा पदक जीतने पर कोच और खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी है। इससे पहले प्रीति ने 2023 में नेशनल प्रतियोगितायों में छह स्वर्ण पदक जीते थे। ये पदक उन्होंने पहली बार खेलो इंडिया गेम्स के दोनों इवेंट में जीते थे। इसके अलावा बंगलुरु में हुई ओपन नेशनल चैपियनशिप में भी उन्हें एक स्वर्ण पदक मिला था। इसके अलावा जापान में हुई विश्व एथलेटिक्स में भी उन्होंने दो कांस्य पदक जीते थे।

गंभीर ने अपनी पसंदीदा टीम में रोहित, बूमराह को शामिल नहीं किया

विराट , सचिन , सहवाग व द्रविड़ को मिली जगह

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अपनी पसंदीदा अंतिम ग्यारह टीम घोषित की है। हैरानी की बात ये है कि गंभीर ने इसमें रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल नहीं किया है। टीम में विराट कोहली के अलावा पूर्व बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग , सचिन तेंदुलकर और पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ भी शामिल किया गया है। गंभीर ने इसमें पारी की शुरुआत के लिए वीरेंद्र सहवाग के साथ स्वयं अपने को रखा है। विराट इसमें 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। गंभीर को हमेशा ही लीक से हटकर चलने के लिए जाना जाता है। उनकी खूबी है कि है कि वो जो भी करते हैं दिल से करते हैं और जो सोचते हैं वो बिना किसी डर के साफ बोल देते हैं। ऐसा ही उनकी इस टीम को देखकर भी अंदाज होता है। इसमें विराट कोहली को तो जगह मिली लेकिन रोहित बाहर रह गये। गंभीर ने इस टीम में अनिल कुंबले और आर अश्विन जैसे दो स्पिनर हैं जबकि तेज गेंदबाजी के लिए जहीर खान और ऑलराउंडर इरफान पठान को रखा है। भी ऑल टाइम इलेवन में नहीं हैं।

गंभीर का एक वीडियो भी आया है। इसमें उनको जब अपनी पसंदीदा टीम का चयन करने को कहते हैं तो वह अंतिम ग्यारह में सहवाग के साथ स्वयं ओपनर के तौर पर रखा है। गंभीर ने कहा, मैं और सहवाग बतौर सलामी बल्लेबाज टीम में होंगे। द्रविड़, सचिन चौथे नंबर पर जबकि विराट कोहली 5वें स्थान पर उतरेंगे। युवराज सिंह छठे और महेंद्र सिंह धोनी सातवें नंबर पर उतरेंगे। अनिल कुंबले 8, आर अश्विन 9वें नंबर पर, इरफान पठान को मैं 10वें स्थान पर रखना चाहूंगा और जहीर खान अंत में उतरेंगे।

गौतम गंभीर की ऑल टाइम इंडिया इलेवन

गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), अनिल कुंबले, आर अश्विन, इरफान पठान और जहीर खान

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार सोमवार को बढ़त पर बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी होने से बाजार उछला है। दिन भर के कारोबार के बाद आज 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 194.07 अंक करीब 0.24 फीसदी बढ़कर 82,559.84 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 50 0.17 फीसदी करीब 42.80 अंक बढ़कर 25,278.70 के स्तर पर बंद हुआ। इंट्रा डे कारोबार के दौरान आज सेंसेक्स 82,725.28 के उच्च स्तर और निफ्टी 25,333.65 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।

सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डालें तो निफ्टी एफएमसीजी 0.82 फीसदी, निफ्टी आईटी 0.44 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.51 फीसदी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.66 फीसदी के बल पर शेयर बाजार को बढ़त बनाने में सहायता मिली। आज कारोबार के दौरान आईटी इंडेक्स अपने शीर्ष स्तर पर पहुंच गया जबकि निफ्टी मेटल -1.04 फीसदी, फार्मा -0.99 फीसदी, ऑटो -0.39 फीसदी और मीडिया 0.47 फीसदी ने बाजार पर विपरीत दबाव बनाया।

जानकारों के अनुसार अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और नए सिरे से विदेशी पूंजी के प्रवाह घरेलू इक्विटी में तेजी से बाजार को सहायता मिली है।

आज कारोबार के दौरान एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स पर आज 18 शेयर लाभ पर बंद हुए, जबकि निफ्टी के 27 शेयर उछले। सेंसेक्स पर बजाज फिनसर्व के शेयरों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। बजाज फिनसर्व के शेयर आज 3.23 फीसदी की बढ़त के साथ ही 1840.10 रुपये पर बंद हुए। वहीं दूसरे नंबर पर बजाज फाइनेंस में 3.18 फीसदी की बढ़त रही।

इसके अलावा, सेंसेक्स के शीर्ष लाभ वाले शेयरों में एचसीएल टेक, आईटीसी, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, इंफोसिस, अदाणी पोर्ट्स, एसबीआई, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा जैसे शेयर रहे।

वहीं आज सेंसेक्स के सबसे अधिक गिरावट वाले शेयरों में एनटीपीसी के शेयर रहे। इसके शेयर आज 1.57फीसदी की गिरावट के साथ 409.85 रुपये पर बंद हुए। इसके अलावा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएंडएम), भारती एयरटेल, पावरग्रिड, एलएंडटी, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, सनफार्मा, नेस्ले इंडिया, जेडीडब्यलू स्टील और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर गिरावट पर बंद हुए।

दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में, सियोल और टोक्यो के शेयर शेयर उछले जबकि शंघाई और हांगकांग के शेयर नीचे आये अमेरिकी बाजार में भी गिरावट दर्ज की गयी।

इससे पहले आज सुबह बाजार तेजी के साथ खुला।

शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 222 अंक की बढ़त के साथ 82,58.53 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 97.70 अंक की बढ़त के साथ 25,333.60 पर कामकाज कर रहा था।

सोना-चांदी के भाव में सप्ताह के पहले ?दिन आई ?गिरावट

- सोना 71,450 रुपए, चांदी का भाव लगभग 84,150 रुपए

नई दिल्ली (ईएमएस)। इस सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सोने-चांदी के वायदा भाव में नरमी देखने को मिल रही है। दोनों के वायदा सोमवार को गिरावट के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 71,450 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 84,150 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव तेज शुरुआत के बाद सुस्त पड़ गए। सोने के वायदा भाव की शुरुआत नरमी के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रेक्ट 99 रुपये की गिरावट के साथ 71,512 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह 166 रुपये की गिरावट के साथ 71,445 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत सुस्त रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रेक्ट 300 रुपये की गिरावट के साथ 84,910 रुपये पर खुला। इस समय यह 1,050 रुपये की नरमी के साथ 84,160 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। लेकिन बाद में इनके भाव में गिरावट देखी जाने लगी। कॉमेक्स पर सोना 2,536 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,527.60 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 1.80 डॉलर की गिरावट के साथ 2,525.80 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 29.24 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 29.14 डॉलर था। इस समय यह 0.31 डॉलर की गिरावट के साथ 28.83 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

एव4क अरब डॉलर लेकर.....तीन कंपनियों को खरीदने निकले गौतम अडानी

मुंबई (ईएमएस)। हिंडनबर्ग रिसर्च के जिन्न का पीछा छूटने के साथ ही अडानी ग्रुप फिर फ्रंटफुट पर आ गया है। देश के तीसरे बड़े औद्योगिक घराने ने अपने फूड और एमएमसीजी बिजनस को बढ़ाने के लिए एक अरब डॉलर यानी करीब 8,388 करोड़ रुपये का फंड बनाया है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। देश में पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और गौतम अडानी इसका फायदा उठाना चाहते हैं। अडानी ग्रुप के एफएमसीजी कंपनी अडानी विल्मर देश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में कम से कम तीन कंपनियों को खरीदने की तैयारी में है। इसमें रेडी-टु-कुक फूड्स और पैकेज्ड एडिबल ब्रांड्स शामिल हैं।

अडानी विल्मर में अडानी और सिंगापुर के विल्मर ग्रुप की हिस्सेदारी है। इसके पास फॉर्च्यून ऑयल और कोहिनूर राइस ब्रांड है। कंपनी हाल में स्टेक बेचने की तैयारी में थी लेकिन अब वह तेजी से कैपेक्स एक्सपेंडीचर कर रही है। अडानी की योजना कंज्यूमर फेसिंग बिजनस से रेवेन्यू को बढ़ाकर 25 से 30 फीसदी करने की है। इसमें फूड, एमएमसीजी, कमोडिटी और एयरपोर्ट बिजनेस शामिल है। सूत्रों ने बताया कि अडानी विल्मर की अगले दो से तीन साल में कई कंपनियों को खरीदने की योजना है। ग्रुप की नजर खासकर साउथ और ईस्ट के मार्केट पर है। वहां इस साल और अगले साल कम से कम तीन कंपनियों के अधिग्रहण की योजना है।

सूत्र ने कहा कि अडानी ग्रुप की योजना एफएमसीजी बिजनस पर 80 करोड़ से एक अरब डॉलर खर्च करने की योजना है। इसमें से प्रत्येक की वैल्यू कम 20 से 25 करोड़ डॉलर हो सकती है। अडानी विल्मर का पिछले साल रेवेन्यू 51,261.63 करोड़ रुपये रहा। फिलहाल कंपनी की मौजूदगी देश की पश्चिमी, सेंट्रल और उत्तरी राज्यों में है। लेकिन अब कंपनी दक्षिणी और पूर्वी राज्यों पर फोकस कर रही है। कंपनी इन इलाकों की टॉप कंपनियों की खरीदकर वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है। टाटा और रिलायंस के बाद अडानी ग्रुप भारत का तीसरा बड़ा औद्योगिक ग्रुप है।

सरकारी कंपनियों के बोनस शेयर और बायबैक नियमों में होगा बदलाव

- सरकार 2016 के दिशानिर्देशों में करेगी संशोधन

नई दिल्ली (ईएमएस)। शेयर बाजार में लिस्टेड सरकारी कंपनियों के स्टॉक में डिविडेंड, बोनस शेयर और शेयर बायबैक से जुड़े नियमों में सरकार संशोधन करने जा रही है। दरअसल इस मामले में सरकार 2016 के दिशानिर्देशों में संशोधन करने पर काम कर रही है। अधिकारियों ने कहा है कि इस महीने वित्त मंत्रालय द्वारा रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी किए जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने मई 2016 में सीपीएसई में सरकारी निवेश के कुशल प्रबंधन के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन पर डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की थी। एक अधिकारी ने बताया ?कि सीपीएसई अब बहीखाते के मामले में ज्यादा मजबूत हैं और उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में सुधार हुआ है इसलिए अब पूंजी पुनर्गठन दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। जारी किए गए पूंजी पुनर्गठन दिशानिर्देशों के अनुसार जिन सीपीएसई के पास व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपनी पूंजी को अनुकूलतम रूप से निवेश करने की योजना नहीं है, उन्हें अधिशेष निधियों पर पेशेवर रूप से विचार करना चाहिए। निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के मई 2016 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई को मुनाफे का 30 प्रतिशत या कुल परिसंपत्ति का 5 प्रतिशत न्यूनतम एनुअल डिविडेंड देना आवश्यक है। इसके साथ ही कम से कम 2,000 करोड़ रुपये की कुल परिसंपत्ति और 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और बैंक जमा वाले प्रत्येक सीपीएसई को शेयर पुनर्खरीद का विकल्प चुनना जरूरी है। , बोनस शेयर भी तभी जारी किए जाएंगे, जब सीपीएसई के निर्धारित भंडार और अधिशेष उसकी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 10 गुना के बराबर या उससे ज्यादा हो।

सरकार लाएगी रिपेयर इंडेक्स, दिसंबर तक होगा लांच

नई दिल्ली (ईएमएस)। जल्द ही आपको टीवी या मोबाइल खरीदते वक्त पता चल जाएगा कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं वह खराब होने पर आसानी से दोबारा रिपेयर हो जाएगी या आपको उसे ठीक कराने में काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसके लिए सरकार रिपेयर इंडेक्स लाएगी। यह इंडेक्स इस साल दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के रिपेयर सूचकांक से बढ़ती ई-कचरे की समस्या का समाधान होगा और निर्माताओं को अधिक आसानी से मरम्मत योग्य उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इसे बनाएगा। उपभोक्ताओं को यह जानकारी देने के लिए प्रमुख मापदंडों पर स्कोर प्रदान करेगा कि किसी उत्पाद की मरम्मत कितनी आसानी से की जा सकती है। एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए, उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने मंत्रालय के रिपेयर इंडेक्स बनाने की योजना की जानकारी दी। प्रस्तावित सूचकांक अन्य देशों के रिपेयर इंडेक्सेस के अध्ययन के बाद बनाया जा रहा है। फ्रांस का रिपेयर इंडेक्स पांच मानको पर आधारित होता है। यह तकनीकी दस्तावेजों की उपलब्धता, डिसएसेंबली में आसानी, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और कीमत जैसे मानदंडों पर उत्पादों को रेटिंग देता है। भारतीय रिपेयर इंडेक्स भी किसी भी उत्पाद को पांच में से कोई एक रेटिंग देगा। गौरतलब है कि सरकार ने पहले ही एक राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसमें 63 कंपनियां शामिल हैं। भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादक है।

एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक अजय चौधरी ने कार्यशाला में कहा कि आज, अधिकांश उत्पाद मरम्मत योग्य नहीं हैं। हमें ऐसे उत्पाद डिजाइन करने की आवश्यकता है जिन्हें मरम्मत किया जा सके। जब तक हम कानून नहीं बनाते, चीजें नहीं बदलेंगी। इसलिए इस दिशा में कानून बनाने की जरूरत है। मालूम हो कि आजकल बाजार में बिक रहे टीवी-मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत इनकी रिपेयरिंग है। खराब होने पर इनकी मरम्मत आसानी से नहीं होती। कुछ के ओरिजिनल पार्ट्स नहीं मिलते और मजबूरी में घटिया कलपुर्जे डलवाकर काम चलाना पड़ता है।

साउथ ईस्ट एशिया में पैदल यात्री और दो पहिया वाहन वाले ज्यादा हो रहे हादसों का शिकार

नई दिल्ली (ईएमएस)। विश्व स्वास्थ्य संगठन साउथ-ईस्ट एशिया की रिजनल डायरेक्टर साइमा वाजेद ने कहा, हमारे क्षेत्र में सड़क यातायात से होने वाली मौतों में पैदल चलने वालों, साइकिल चलाने वालों और टू-व्हीलर या थ्री-व्हीलर समेत कमजोर रोड यूजर्स की संख्या 66ऽ है। उन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया में पैदल यात्री और दो पहिया वाहन वाले ज्यादा हादसों का शिकार हो रहे हैं।

साइमा वाजेद ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों और उनके नेटवर्क को सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों, बच्चों, किशोरों, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों, पैदल यात्रियों और अन्य कमजोर समूहों को प्राथमिकता देते हुए डिजाइन करने की जरूरत है।

साइमा वाजेद ने यह बात रोड ट्रैफिक से होने वाले हादसों की रोकथाम और सुरक्षा को बढ़ावा देने को लेकर 2 से 4 सितंबर के बीच 15वें वर्ल्ड समिट 'सेफ्टी 2024 में कही। इस समिट की मेजबानी भारत कर रहा है। नई दिल्ली में आयोजित इस समिट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को साउथ ईस्ट एशिया रीजन के देशों से रोड ट्रैफिक और रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों को कम करने के उपायों में तेजी लाने की अपील की। 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में मौत की दर का एक मुख्य कारण रोड ट्रैफिक या रोड एक्सीडेंट को माना जाता है।

इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान -दिल्ली और जॉर्ज इंस्टीटयूट फॉर ग्लोबल हेल्थ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य व तंत्रिका विज्ञान संस्थान के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस सम्मेलन का को-स्पॉन्सर है। 'सेफ्टी 2024समिट का मकसद रोड सेफ्टी, रोड एक्सीडेंट जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल कोशिशों पर फोकस करना है।

पुतिन ने दोस्त किम जोंग उन को क्या भेजा गिफ्ट, जिसकी होने लगी चर्चा

मास्को (ईएमएस)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच गहरी दोस्ती है। इसकारण दोनों एक दूसरे को स्पेशल गिफ्ट भेजते रहते हैं। लेकिन इस बार जो गिफ्ट पुतिन ने किम जोंग उन को दिया है, उसकी खूब चर्चा हो रही है। यह गिफ्ट ओरलोव ट्रॉटर के घोड़े हैं, जिन्हें पुतिन ने किम जोंग उन को सवारी करने के लिए भेजा है।

दरअसल किम को ओरलोव ट्रॉटर नस्ल के घोड़े पसंद हैं। पहले भी वे इसकी सवारी करते दिखाई दिए हैं। लेकिन इस बार का गिफ्ट खास है। दरअसल, तानाशाह ने यूक्रेन युद्ध के लिए अपने हथियार भंडार खोल दिए हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद रूस को भेजा है, ताकि रुस यूक्रेन से जंग लड़ सके। पुतिन ने अपने दोस्त के इसी एहसान का बदला गिफ्ट देकर चुकाया है। उन्होंने कोरियाई नेता किम जोंग-उन को 24 शुद्ध नस्ल के घोड़े भेजे हैं। इसमें 19 घोड़े, 5 घोड़ियां हैं।

कुछ दिनों पहले जब पुतिन उन से मिलने के लिए उत्तर कोरिया गए थे, तब किम जोंग उन ने उन्हें पुंगसन कुत्ते गिफ्ट किए थे। यह शिकारी कुत्ता है, जो टाइगर का भी शिकार कर लेता है। तब पुतिन किम को गिफ्ट देने के लिए अपने साथ बकरियां लेकर गए थे। हालांकि, दो साल पहले, प्योंगयांग को 30 ओरलोव ट्रॉटर्स भी मिले थे और किम को एक प्रचार वीडियो में एक सफेद घोड़े की सवारी करते हुए देखा गया था। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं।

बांग्लादेश में हिंसा के पीछे पाकिस्तान तो नहीं? यूनुस सरकार के साथ कर रहा बैठकें

ढाका,(ईएमएस)। पाकिस्तान अब बांग्लादेश में अपनी सक्रियता बढ़ाता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में पाकिस्तानी दूतावास और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। बांग्लादेश में हुई हिंसा में पाकिस्तान की भूमिका होना संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में रह रही हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेश में सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है। कुछ हफ्तों से पाकिस्तान दूतावास अंतरिम सरकार के सदस्यों के साथ बैठकें कर रहा है। खबरें हैं कि इस दौरान बाढ़ राहत से लेकर छात्र एक्सचेंज प्रोग्राम तक को लेकर उच्चायोग के अधिकारियों और नई सरकार के सदस्यों के बीच बातचीत हुईं है। पाकिस्तान उच्चायोग ने इससे जुड़ी जानकारी भी सोशल मीडिया पर साझा की है।

पाकिस्तान उच्चायोग ने एक्स पर लिखा- बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद नाहिद इस्लाम और आसिफ मोहम्मद शोजिब से मिलकर अच्छा लगा। मीडिया, स्पोर्ट्स, युवा और संस्कृति और आईटी के क्षेत्र में सहयोग समेत साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की कुछ तस्वीरें भी शेयर की गईं हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बात की थी। कहा जाता है कि हसीना के प्रधानमंत्री रहते दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के बीच कम ही मौकों पर बात हुई थी।

ग़ाज़ा में बंधकों के शव मिलने के बाद भड़की नाराज़गी

यरुशलम(ईएमएस)। ग़ाज़ा में छह बंधकों के शव मिलने के बाद हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जो सरकार की नीतियों से नाखुश हैंइसराइल में प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी तेल अवीव, यरूशलम, और अन्य शहरों में इकट्ठा होकर इसराइली झंडे लहराते हुए नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार हमास के साथ जल्द से जल्द समझौता कर बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करे।ग़ौरतलब है कि आईडीएफ (इसराइल डिफेंस फोर्स) ने शनिवार को दक्षिणी ग़ज़ा के रफाह में एक सुरंग में छह बंधकों के शव बरामद किए थे। आईडीएफ का कहना है कि वे जब तक इन बंधकों तक पहुंच पाते, उससे पहले ही उन्हें मार दिया गया था। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है, जिससे नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध और तेज़ हो गया है। प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण रही, लेकिन बाद में यह उग्र हो गया। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरियर तोड़ दिए और प्रमुख हाईवे को ब्लॉक कर दिया। टायर जलाकर विरोध जताया गया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इसराइल की ट्रेड यूनियन ने भी सोमवार को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। वे भी यही मांग कर रहे हैं कि बंधकों की रिहाई के लिए सरकार जल्द से जल्द हमास के साथ समझौते की प्रक्रिया को तेज़ करे।

पुतिन और जेलेंस्की ने बना लिया एक दूसरे के यहां तबाही का प्लान, बस एक इशारे का है इंतजार

कीव(ईएमएस)। रूस-यूक्रेन जंग में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और कौन किस पर भारी पड़ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस में तबाकी प्लान बनाने में जुटे हैं। उन्हें केवल अमेरिका से मंजूरी मिलने का इंतजार है। खबरों के मुताबिक, जेलेंस्की ने कहा कि शुक्रवार को खार्किव में गाइडेड एरियल बमों से 6 लोगों की मौत हो गई और 97 लोग घायल हो गए। शनिवार को भी इसी तरह के कई हमले हुए। जेलेंस्की ने कहा कि इन इन हमलों को केवल रूसी सैन्य हवाई क्षेत्रों, रूसी सेना के ठिकानों और उनके रसद-हथियारों पर हमला करके ही रोका जा सकता है। जेलेंस्की को अपने प्लान के लिए केवल अमेरिका की इजाजत का इंतजार है। अपने वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने कहा कि हम इस बारे में अपने सहयोगियों से हर दिन बात करते हैं। हम उन्हें मनाते हैं। हम दलीलें पेश करते हैं।

जेलेंस्की ने अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका उसे रूसी एयरफील्ड्स और बेस पर हमला करने की मंजूरी दे। इस बाबत यूक्रेनी डेलिगेशन ने अमेरिका में सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की। जी हां, यूक्रेन ने अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह कीव को रूसी क्षेत्र के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति दे। जेलेंस्की ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से अपील करते हुए कहा कि हमें यूक्रेन और यूक्रेनी लोगों की सही मायने में और पूरी तरह से रक्षा करने की क्षमता चाहिए। हमें लंबी दूरी की क्षमताओं और आपके लंबी दूरी के गोले और मिसाइलों के लिए अनुमति, दोनों की जरूरत है। उन्होंने साफ कहा कि हमने अपनी डिटेल सहयोगी देशों को भेज दी है कि हमें क्या-क्या चाहिए। माना जा रहा है कि जेलेंस्की का प्लान तैयार है। वह रूस पर हमला करने को पूरी तैयारी कर चुके हैं। मगर इसे अंजाम देने के लिए उन्हें अमेरिका की हां का इंतजार है। हालांकि, पुतिन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हैं। वह भी पूरी तैयारी में हैं। बीते एक सप्ताह से तो ताबड़तोड़ अटैक भी कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले जेलेंस्की ने कहा था कि उनके पास जंग खत्म करने का प्लान है। जेलेंस्की राष्ट्रपति जो बाइडन को जीत वाला प्लान बताएंगे। साल 2022 से लेकिन अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 50 बिलियन डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता प्रदान की है, मगर अपने हथियारों के इस्तेमाल को यूक्रेनी धरती और रक्षात्मक सीमा पार अभियानों (डिफेंसिव क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन) तक सीमित रखा है। यानी अमेरिका ने अब तक अपने हथियारों को रूस के भीतर दुश्मन देश पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी है। मगर अब जेलेंस्की चाहते हैं कि वह अमेरिकी हथियारों से पुतिन के घर को धुआं-धुआं कर दे।

हेलिकॉप्टर के पहाड़ से टकराने से हुई थी ईरान के राष्ट्रपति की मौतः रिपोर्ट

- जांच के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या हमले का कोई सबूत नहीं मिला

तेहरान (ईएमएस)। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हेलिकॉप्टर दुर्घटना में हुई थी। उनकी मौत पर संशय बना हुआ था कि आखिर उनका हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है। दरअसल जिस समय उनकी मौत हुई थी उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें उनके दुश्मन देशों का हाथ हो सकता है लेकिन ईरान के सरकारी टीवी ने इस घटना पर अंतिम जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हेलिकॉप्टर दुर्घटना में रईसी की मौत मुख्य रूप से घने कोहरे सहित मौसम की स्थिति के कारण हुई थी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एक कट्टरपंथी, जिन्हें सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था, उनकी मई में अज़रबैजान सीमा के पास एक पहाड़ी क्षेत्र में उनके हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई थी। ईरान की सेना द्वारा घटना की जांच के लिए नियुक्त एक उच्च समिति द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि घने कोहरे के कारण रईसी और उनके साथियों को ले जा रहा हेलिकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया। ईरान की सेना द्वारा मई में दी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया था कि जांच के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। अगस्त में, फ़ार्स समाचार एजेंसी ने 19 मई की दुर्घटना के मुख्य कारणों को ख़राब मौसम की स्थिति और सुरक्षा प्रोटोकॉल के विरुद्ध दो अतिरिक्त यात्रियों के साथ हेलिकॉप्टर के ऊपर चढ़ने में असमर्थता बताया था लेकिन ईरानी सशस्त्र बलों ने इस रिपोर्ट को तुरंत खारिज करते हुए कहा ?कि न्यूज़ पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के विरुद्ध हेलिकॉप्टर में दो लोगों की मौजूदगी के बारे में जो उल्लेख किया गया है, वह पूरी तरह से झूठ है।

140 सेकेंड की क्लिप से हिल गया पाकिस्तान......मुनीर का करीब दे रहा बयान

लौहार (ईएमएस)। पाकिस्तान की राजनीति दहशतगर्दी की बैसाखी के सहारे टिकी हुई है। पाकिस्तान दुनिया को इकलौता ऐसा देश है जहां आतंकवाद की दो कैटेगरी है। अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद। अच्छा आंतकवाद वहां जिसे पाकिस्तान सेना का समर्थन हासिल है और बुरा आंतकवाद वहां जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ काम करता है। इसमें सबसे बड़ा नाम तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी का है। पाकिस्तान में आतंकियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सेना भी उनके आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर है। हाल ही में अलगाववादियों ने बलूचिस्तान में कई बसों को रोककर आईडी कार्ड दिखाकर दर्जनों पंजाबी मजदूर की हत्या की थी। इस वारदात के बाद पाकिस्तान के सीमांत प्रांत खैबर पख्तूनवा में सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके दो भाईयों को टीटीपी के आतंकियों ने किडनैप किया था।

पाक सेना के अफसर की रिहाई के बदले आतंकियों ने अपने छह साथियों की रिहाई के साथ ही 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए भी वसूल किए हैं। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल और तीन नागरिकों को छुड़ाने की एवज में पाकिस्तान सरकार को छह टीटीपी आतंकी और 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए भी फिरौती देनी पड़ी हैं।

गौरतलब है कि 28 अगस्त को डेरा इस्माइल खां से टीटीपी ने लेफ्टिनेंट कर्नल खालिदा मीर और उनके 3 रिश्तेदारों को अगवा किया था। टीटीपी ने उनका वीडियो जारी किया था जिसमें वे पाकिस्तानी सेना से अपनी खैरियत बताकर टीटीपी की मांग को पूरा करने का अनुरोध कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने इसकी जानकारी दी। जिन टीटीपी आतंकियों ने इन चार लोगों को अगवा किया था वे टीटीपी के गंडापुर गुट के थे।

लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि मुनीर की सेना के जिस फौजी को टीटीपी ने रिहा किया है। वहां लेफ्टिनेंट कर्नल तहरीक-ए-तालिबान की तारीफों के पुल बांध रहा है। 140 सेकेंड की क्लिप देखकर रावलपिंडी में बैठे जनरल मुनीर के होश उड़े हुए है। टीटीपी की तारीफों के कसीदे पढ़ रहा ये लेफ्टिनेंट कर्नल 72 घंटे पहले तक मुनीर का करीबी हुआ करता था। लेकिन तहरीक-ए-तालिबान की कैद में इसका हृदय परिवर्तन हो गया। मुनीर का लेफ्टिनेंट कर्नल जिस टीटीपी की तारीफें कर रहा है। वही आतंकी संगठन है जो पाक सेना के जवानों को चुनचुनकर मारता है। खुलकर शहबाज शरीफ का विरोध करता है।

रूस ने कीव में किए ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले

कीव (ईएमएस)। यूक्रेन की वायु सेना ने बताया कि रूस ने कीव और संभवतः अन्य शहरों को निशाना बनाकर ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से कई हमले किए हैं। सोमवार तड़के राजधानी कीव कई विस्फोटों से दहल उठी, जिससे निवासियों को बम रोधी आश्रयों में शरण लेनी पड़ी।

कीव के मेयर विताली क्लित्स्को ने कहा कि कीव के होलोसिव्स्की और सोलोमिंस्की में आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि शेवशेनकिव्स्की जिले में मलबे के नीचे दबने से एक व्यक्ति के जख्मी होने की सूचना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख आंद्री यरमाक ने पोस्ट में कहा, हर चीज का जवाब मिलेगा। दुश्मन को इसका एहसास होगा। वायु सेना के अनुसार, रूस ने कीव को निशाना बनाकर कई क्रूज मिसाइल के साथ बैलिस्टिक मिसाइल दागीं और कुछ ड्रोन हमले भी किए।

भारत की बात से तिलमिलाया पाकिस्तान पहुंचा यूएन,कश्मीर पर फिर उगला जहर

जेनेवा(ईएमएस)। पाकिस्तान आए दिन कश्मीर के रास्ते भारत में आतंकियों को भेजता है और भारत में अशांति फैलाने का मंसूबा रखता है। लेकिन भारत उसके हर मंसूबे पर पानी फेर देता है। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। हमेशा की तरह उसने कश्मीर को लेकर यूएन का राग अलापा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने रविवार को कहा कि कश्मीर विवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मुद्दा है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार हल किया जाना चाहिए। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जम्मू-कश्मीर पर हाल ही में की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए यह टिप्पणी की।

रविवार को, पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता बलूच ने कहा कि जम्मू और कश्मीर ''विवाद एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार हल किया जाना चाहिए। इस अनसुलझे संघर्ष का समाधान दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया कि जम्मू और कश्मीर विवाद एकतरफा सुलझाया जा सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान कूटनीति और बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देगा। उन्होंने एक बयान में कहा, ''दक्षिण एशिया में सच्ची शांति और स्थिरता केवल यूएनएससी प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों के अविभाज्य अधिकारों के अनुसार समझौते के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। मालूम हो कि जयशंकर ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग समाप्त हो गया है। कार्रवाई के परिणाम होते हैं, और जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया है। आज मुद्दा यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते पर विचार कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम निष्क्रिय नहीं हैं और चाहे घटनाएं सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में जाएं, हम किसी भी तरह से प्रतिक्रिया करेंगे।गौरतलब है कि भारत ने बार-बार पाकिस्तान से कहा है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश ''हमेशा देश का अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे''। भारत द्वारा 5 अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई। भारत ने बार-बार कहा है कि वह आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है।

नेतन्याहू को अब अर्थव्यवस्था चौपट होने का सताने लगा डर

येरुशलम,(ईएमएस)। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है लेकिन जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही घर में घिर गए हैं। इजरायल के सबसे बड़ा मजदूर संघ इजरायली बंधकों को वापस लाने के लिए दबाव डाल रहा है। इसी दवाब को और तेज करते हुए मजदूर संघ के प्रमुख ने आज बंद बुलाया है।

एक दिवसीय आम हड़ताल के आह्वान को इज़रायल के मुख्य निर्माताओं और हाई-टेक क्षेत्र के उद्यमियों ने समर्थन दिया है। इजरायल की अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली आवाज़ों में से कुछ के गठबंधन ने पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के उग्रवादियों द्वारा पकड़े गए लोगों में से छह बंधकों की मौत पर जनता के गुस्से के पैमाने को दर्शाते हैं। रविवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने यरुशलम और तेल अवीव में सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि छह लोगों की मौत, लड़ाई रोकने और अपने प्रियजनों को घर वापस लाने के लिए नेतन्याहू ने हमास से समझौता करने में विफलता का सीधा परिणाम है।

भारत को तय करना है हसीना को लौटाएं या नहीं: यूनुस सरकार

ढाका(ईएमएस)। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत की शरण में हैं। बांग्लादेश बार बार हसीना को सौंपने की मांग करता रहा है। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री तौहीद हुसैन का कहना है कि अगर उनके देश की अदालत आदेश जारी करें तो वो पूर्व पीएम शेख हसीना को भारत से वापस लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह भारत पर निर्भर करता है कि वह हसीना को वापस भेजे या नहीं। सरकार के निर्देश पर हसीना के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे हो गए हैं। बीते 5 अगस्त से हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। उधर, बांग्लादेश की यूनुस सरकार हसीना समेत उनकी पार्टी अवामी दल के कई नेताओं और पूर्व कैबिनेट मंत्रियों के राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर चुकी है।

हुसैन ने कहा कि यह भारतीय पक्ष पर निर्भर करेगा कि वह हसीना को वापस भेजे या नहीं। हुसैन ने कहा, ''यह भारत को तय करना है कि वह उसे लौटाएगा या नहीं। हमारा उनके साथ एक समझौता है और समझौते के अनुसार, भारत चाहे तो उन्हें वापस कर सकता है। हालांकि, उस देश में भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं और हमें उन कानूनी प्रक्रियाओं के अनुपालन में उसे वापस लाने का प्रयास करना होगा।तौहीद हुसैन ने विदेश मंत्रालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, अगर देश की अदालतें मुझे उन्हें (शेख हसीना) वापस लाने की व्यवस्था करने के लिए कहती हैं, तो मैं वह व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। छात्रों के नेतृत्व में हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश में 600 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 5 अगस्त को देश छोड़कर भागने के बाद से हसीना, पूर्व मंत्रियों और उनकी अवामी लीग पार्टी के नेताओं के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से हत्या, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार शामिल हैं।

जब हुसैन से राजनयिक पासपोर्ट रद्द किए जाने के बाद भारत में हसीना की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर भारत से पूछें, वे आपको बता सकते हैं कि शेख हसीना भारत में किस स्थिति में हैं।बांग्लादेश में भारत समर्थित विकास परियोजनाओं पर ठप पड़े कामों को लेकर पूछे सवाल के जवाब में हुसैन ने कहा, ''देखिए, यह निर्विवाद है कि किसी भी क्रांतिकारी गतिविधि के बाद कुछ अस्थिरता हो सकती है। हमारे सामने कुछ कानूनी समस्याएं थीं, लेकिन हम उन्हें नियंत्रण में लाने में कामयाब रहे। धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा और वे (भारतीय) भी लौट आएंगे।

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि

2013 में, बांग्लादेश और भारत ने एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें दोनों पड़ोसी देश के बीच भागे हुए अपराधियों और आतंकवादियों को सौंपने को लेकर समझौता हुआ था। दोनों पक्षों ने अतीत में संधि के तहत अपराधियों का आदान-प्रदान किया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अभी औपचारिक रूप से भारत से हसीना को वापस भेजने का अनुरोध नहीं किया है। हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने कहा है कि हसीना सुरक्षा कारणों से बहुत कम समय के नोटिस पर देश में आईं हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने बांग्लादेश द्वारा उनके प्रत्यर्पण की मांग की संभावना पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और इसे एक काल्पनिक मुद्दा बताया।

गुजरात में मानसून की अब तक हो चुकी 111.43 फीसदी बारिश, 132 डेम हाई अलर्ट पर

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात में दो-तीन दिनों की राहत के बाद फिर एक बार राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया हैं मौसम विभाग की मानें तो अगले 5 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती हैं गुजरात में अब तक मानसून सीजन की 111.43 प्रतिशत औसत बारिश हो चुकी हैं राज्य में और ऊपरी हिस्सों में हुई अच्छी बारिश के चलते गुजरात के 132 जलाशय पानी से लबालब होने पर हाईअलर्ट पर हैं पिछले सप्ताह लगातार हुई बारिश के कारण राज्य की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, जिनमें 357 रास्ते अब बंद हैं, इस कारण कई जिलों में परिवहन सेवा प्रभावित हुई हैं दूसरी ओर गुजरात में फिर एक बार मेघा की धुआंधार बेटिंग शुरू हो गई हैं उडीसा के डिप्रेशन के असर के चलते राज्य के कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही हैं खासकर सोनगढ़ में 8 इंच, वघई में 7 इंच, वांसदा, उच्छल, डोलवण और व्यारा में 6-6 इंच, सुबीर में 5 इंच, आह्वा में 4 इंच, वालोड में 3 इंच, मोरवाहडफ, लीमखेडा, जेतपुरपावी में 2-2 बारिश होने की खबर हैं आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे के दौरान राज्य की 72 तहसीलों में बारिश दर्ज हुई हैं गुजरात में अब मानसून सीजन की औसत 111.43 प्रतिशत बारिश हो चुकी हैं राज्य की 87 तहसीलों में औसत 40 इंच से अधिक बारिश दर्ज हुई हैं जबकि 124 तहसीलों में औसत 20 से 40 इंच और 39 तहसीलों में 10 से 20 इंच बारिश दर्ज हुई अबकी बार मानसून की सीजन की सबसे अधिक बारिश कच्छ अंचल में 179.34 प्रतिशत हुई हैं जबकि सौराष्ट्र अंचल में 125.01 प्रतिशत, दक्षिण गुजरात में 111.82 प्रतिशत और उत्तर गुजरात में सबसे कम 88.35 प्रतिशत बारिश हुई राज्य और ऊपरी हिस्सों में हुई अच्छी बारिश से ज्यादातर जलाशय छलक गए हैं जिनमें 132 जलाशयों को हाई अलर्ट और 15 को अलर्ट पर रखा गया हैं गुजरात की जीवन रेखा सरदार सरोवर में 86.12 फीसदी जल भंडारण हो चुका हैं वहीं, राज्य के कुल 206 जलाशयों में 78.45 फीसदी जल भंडारण हो चुका हैं राज्य में 113 बांध 100 प्रतिशत और 43 बांध 70 से 100 प्रतिशत जबकि 18 बांध 50 से 70 प्रतिशत भरे हुए हैं। भारी बारिश के कारण 23 नदियां और 6 झीलें उफान पर हैं। राज्य में फिलहाल एनडीआरएफ की 15 और एसडीआरएफ की 27 टीमें काम कर रही हैं दूसरी ओर राज्य में लगातार बारिश के कारण कुल 357 सड़कें अभी भी बंद हैं जबकि 21 स्टेट हाईवे और 29 अन्य सड़कें अभी भी बंद हैं पंचायत के स्वामित्व वाले 305 और 2 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं। जानकारी के मुताबिक, अहमदाबाद के कच्छ और छोटाउदेपुर में 1-1 नेशनल हाईवे, आणंद, पाटन में 1-1 स्टेट हाईवे, कच्छ में 4, सुरेंद्रनगर में 3, खेड़ा में 2 स्टेट हाईवे और राजकोट जिले में 3 स्टेट हाईवे बंद हैं राज्य में परिवहन सेवाओं की बात करें तो राज्य में 29 मार्गों पर एसटी की 70 यात्राएं अभी भी रद्द हैं। कच्छ में 10 रूटों पर सबसे ज्यादा 33 ट्रिप जबकि खेड़ा में 4, आणंद में 3, पोरबंदर में 6 ट्रिप बंद हैं। जूनागढ़ में 2 रूटों पर एसटी की 7 यात्राएं रद्द कर दी गई हैं

गुजरात सरकार की हड़ताली डॉक्टरों को काम पर लौटने की चेतावनी, वर्ना होगी कार्रवाई

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात सरकार ने स्टाइपेंड को लेकर हड़ताल पर उतरे डॉक्टरों को कल सुबह 9 बजे तक काम लौटने की चेतावनी दी हैं आदेश का पालन नहीं करने पर डॉक्टरों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी डॉक्टरों के हड़ताल पर उतरने से मरीजों की मश्किलें बढ़ गई हैं बता दें कि गुजरात सरकार ने शनिवार को राज्य के इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड में 20 फीसदी वृद्धि की घोषणा की थी हांलाकि डॉक्टर इस वृद्धि से खुश नहीं हैं रेजिडेंट डॉक्टरों का आरोप है कि स्टाइपेंड में बढ़ोतरी बहुत कम हैं डॉक्टरों की शिकायत है कि 5 साल में 40 फीसदी बढ़ने की बजाय सिर्फ 20 फीसदी ही बढ़ोतरी हुई हैं जो स्टाइपेंड 3 साल के लिए दिया जाना था उसे 5 साल के लिए दिया गया और वो भी कम है इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं राज्य सरकार ने हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टरों को अल्टीमेटम दिया हैं सरकार ने डॉक्टरों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि कल सुबह 9 बजे तक डयूटी ज्वाइन नहीं करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी अब देखना यह है कि सरकार के अल्टीमेटम के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होती है या नहीं सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राज्य सरकार द्वारा कल राज्य के इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है। पहले मिलने वाले स्टाइपेंड में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई हैं इसके बाद जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने राज्य सरकार को कल से 40% स्टाइपेंड बढ़ोतरी के लिए हड़ताल पर जाने की धमकी दी है, जो पूरी तरह से अनुचित है। मरीज़ों के इलाज की कीमत पर उनका निर्णय अमानवीय है। वास्तविक स्थिति यह है कि देश में रेजिडेंट डॉक्टरों को सबसे ज्यादा स्टाइपेंड देने वाले राज्यों में गुजरात अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे है। गुजरात में इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों को दिया जाने वाला स्टाइपेंड़ पूरी तरह से कर मुक्त है, जबकि इन रेजिडेंट डॉक्टरों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर के वेतन पर भी टैक्स लगता है। रेजिडेंट डॉक्टरों को लंबे समय से 1 लाख रुपये से ज्यादा का स्टाइपेंड दिया जा रहा है, इसमें भी सरकार ने 20 फीसदी बढ़ोतरी कर 1,30,000 रुपये कर दिया हैं देश के कई राज्यों में 40 हजार से 70 हजार के स्टाइपेंड के मुकाबले गुजरात में रेजिडेंट डॉक्टरों को दिया जाने वाला स्टाइपेंड 1 लाख रुपये से भी ज्यादा हैं इसके अतिरिक्त, अन्य राज्यों में तीन साल के बांड हैं, जबकि गुजरात में एक साल के बांड हैं। इन रेजिडेंट डॉक्टरों को इन इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों को पढ़ाने वाले संविदा प्रोफेसरों की तुलना में स्टाइपेंड के रूप में अधिक राशि का भुगतान किया जाता है। इनकी रेजिडेंसी डॉक्टरों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर से अधिक स्टाइपेंड पाने की मांग पूरी तरह से अनुचित है।

गुजरात के 4 शहरों में 30 गंगनचुंबी इमारतों को मंजूरी, राज्य को मिला 1000 करोड़ का राजस्व

* अहमदाबाद में 25 गगनचुंबी इमारतें बनेंगी; सूरत और गांधीनगर में 2-2; वडोदरा में 1

* इनमें से 20 आवासीय, 7 कॉमर्शियल, 2 मिक्स-यूज़्ड और 1 सार्वजनिक भवन का होगा निर्माण

गांधीनगर (ईएमएस) आधुनिक विकास के युग में गगनचुंबी इमारतें अपनी विशेष पहचान रखती हैं, इसलिए इसे सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 3 सितंबर को इंटरनेशनल स्कायस्क्रैपर डे मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात गगनचुंबी इमारतों के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उल्लेखनीय है कि गुजरात अपनी विशेष स्कायस्क्रैपर पॉलिसी के बदौलत गुजरात ने पिछले कुछ सालों में स्कायस्क्रैपर प्रोजेक्ट्स से 1000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने में भी सफलता पाई है। आपको बता दें कि वर्ष 2017 तक, गुजरात में इमारतों के लिए अधिकतम 70 मीटर की ऊँचाई अनुमेय थी। शहरी विस्तार की आवश्यकता और वर्टिकल ग्रोथ की क्षमता को पहचानते हुए, राज्य सरकार ने नियमों को संशोधित कर इस दिशा में प्रगतिशील कदम उठाए हैं। राज्य सरकार की स्कायस्क्रैपर पॉलिसी के लागू होने के बाद राज्य में 100 मीटर से अधिक ऊँची प्रतिष्ठित संरचनाओं के निर्माण को प्रोत्साहन मिला है। 27 मई 2021 को लागू स्कायस्क्रैपर पॉलिसी ने अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा और गांधीनगर जैसे प्रमुख शहरों में गगनचुंबी इमारतों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

राज्य सरकार की यह नीति 5.4 के अधिकतम फ्लोर स्पेस इंडेक्स (इएघ) के साथ ऊंची इमारतों के निर्माण की मंजूरी देती है। बेस इएघ के अलावा प्रीमियम इएघ रेडी रेकनर दर के 50% पर उपलब्ध है, जो डेवलपर्स को वर्टिकल ग्रोथ में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन नियमों के लागू होने के बाद से अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर और वडोदरा में 30 गगनचुंबी इमारतों को मंजूरी दी गई है। गुजरात की फाइनेंशियल टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी ने पहले ही दो गगनचुंबी इमारतों का निर्माण पूरा कर लिया है, और अन्य 10 निर्माणाधीन हैं। इन प्रोजेक्ट्स से गुजरात ने वर्टिकल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण राजस्व सृजन में सफलता हासिल की है। गुजरात ने स्थानीय निकायों के प्रीमियम इएघ के माध्यम से लगभग ?1000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। राज्य के शहरी परिदृश्य को सुंदर बनाने वाली ऐसी कई परियोजनाएं इस वर्ष दिवाली से पहले पूरी होने की उम्मीद है। ये इमारतें न केवल ऊंचाई में नए रिकॉर्ड बना रही हैं, बल्कि इनमें मिवन फॉर्मवर्क, शियर वॉल और छत के स्तर पर स्काईवॉक जैसी उन्नत निर्माण तकनीकें भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि ये विकास भविष्य के लिए तैयार हैं।

शहरी विकास और शहरी आवास विभाग के प्रधान सचिव अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक स्पेशल टेक्निकल कमेटी (एऊण) की स्थापना की गई है, जो ऊंची इमारत परियोजनाओं की व्यवहार्यता का आकलन करेगी। इस समिति में सॉयल मिकेनिकल, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और फायर सर्विस के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि इन गगनचुंबी इमारतों में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बने। इनमें से कई गगनचुंबी इमारतों को हरित इमारतों के रूप में भी दर्जा दिया गया है, जो शहरी विकास में सततता में योगदान देती हैं और नए निर्माण के अंतर्गत होने वाले पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करती हैं।

गुजरात के स्कायलाइन में हो रहे ये परिवर्तन अहमदाबाद के सरखेज-गांधीनगर राजमार्ग जैसी प्रमुख सड़कों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहाँ कॉमर्शियल स्पेस डेवलपमेंट में उछाल देखा जा रहा है। अब उच्च इएघ उपलब्ध होने के साथ, यह क्षेत्र गगनचुंबी इमारतों का केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो कुशल भूमि उपयोग और शहरी विकास सततता के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज जब दुनिया इंटरनेशनल स्कायस्क्रैपर डे मना रही है तो ऐसे में गुजरात भी इस विशेष दिवस पर अपनी विशेष पहचान लिए खड़ा है। राज्य में हो रहे नए वर्टिकल डेवलपमेंट्स न केवल आवासीय और कॉमर्शियल स्पेस की बढ़ती मांग को पूरा कर रहे हैं, बल्कि ये वास्तुकला विरासत में एक नया अध्याय लिखने के लिए मंच तैयार कर रहे हैं।

9 साल की छात्रा से शारीरिक छेड़छाड़ के मामले में विधर्मी शिक्षक गिरफ्तार

खेडा (ईएमएस) राज्य में शिक्षा क्षेत्र को शर्मसार करने वाली एक और घटना सामने आई हैं शिक्षक ही अगर विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के बजाए उसके साथ गंदी हरकतें करेंगे तो किसके भरोसे पर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे ताजा घटना खेडा जिले के कठलाल की है, जहां विधर्मी शिक्षक सैयद अख्तरअली ने कक्षा 4 में पढ़नेवाली 9 साल की छात्रा से शारीरिक छेड़छाड़ की घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भड़क उठा और मामला पुलिस थाने पहुंच गया पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक सैयद अख्तरअली को गिरफ्तार कर लिया घटना को लेकर स्थानीय लोगों के साथ हिन्दू धर्म सेना के नेता भी पुलिस थाने पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की साथ ही आरोपी शिक्षक को तुरंत बर्खास्त करने और उसके घर पर बुलडोजर कार्यवाही करने की भी मांग की

गुजरात सरकार ने एक और अधिकारी की छुट्टी की, रिश्वतखोरी के मामले में हुई कार्यवाही

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात सरकार ने राज्य के एक और अधिकारी की छुट्टी कर दी हैं दो लाख की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार सूरत के क्लास वन अधिकारी के खिलाफ ने बड़ी कार्यवाही की हैं दरअसल गुजरात सरकार ने गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज रिश्वतखोरी के एक मामले में क्लास 1 अधिकारी की सेवा समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पिछले जून माह में खान एवं खनिज विभाग सूरत के सहायक निदेशक-उड़न दस्ता नरेश जानी के खिलाफ बिचौलिए के माध्यम से 2 लाख रुपये की रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया था। सूरत एसीबी ने बिचौलिए कपिल प्रजापति की गिरफ्तारी के बाद से फरार चल रहे नरेश कुमार मावजी जानी को गत 29 जुलाई को अदालत में पेशी के दौरान गिरफ्तार किया था एसीबी ने रिश्वत मामले की जांच के निष्कर्षों को लेकर सरकार के संबद्ध विभाग को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसके आधार पर क्लास वन अधिकारी नरेश जानी को बर्खास्त कर दिया गया हैं सूरत के भाठा इलाके में रॉयल्टी परमिट के आधार पर रेत खनन का काम कर रही द सूर्यपुर लेबर्स एंड वर्क कंपनी सोसायटी के मैनेजर ने एसीबी से शिकायत की थी कि खान एवं खनिज विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड के सहायक निदेशक नरेश जानी और बिचौलिए कपिल प्रजापति ने खनन कार्य में बाधा नहीं डालने के लिए 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगी हैं इस शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने 11 जून को सूरत में कपिल परसोत्तम प्रजापति को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था जबकि इस मामले में फरार नरेश जानी ने सूरत के सेशन कोर्ट और फिर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली अग्रिम जमानत नहीं मिलने पर आखिरकार नरेश जानी ने 29 जुलाई को सत्र न्यायालय सूरत में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। सरकारी डयूटी के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में फंसे नरेश कुमार जानी पर एसीबी ने गुजरात सरकार को रिपोर्ट भेजी थी इस रिपोर्ट के आधार पर गुजरात सरकार ने एक महत्वपूर्ण और अनुकरणीय निर्णय लेते हुए रिश्वत मामले के आरोपी नरेश जानी की सेवा गत 11 जून 2024 से समाप्त करने का आदेश दिया हैं नरेश जानी फिलहाल रिश्वत मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

सट्टा-डब्बा कारोबार का प्रभारी हर्षित जैन पैसे दुबई भेजता था

अहमदाबाद , माधुपुरा से पकड़े गए 2300 करोड़ रुपये के डब्बा ट्रेडिंग और क्रिकेट सट्टा नेटवर्क के मुख्य सरगना हर्षित जैन का स्टेट मॉनिटरिंग सेल को अब तक कोई लिंक नहीं मिला है। ठक्कर से प्रारंभिक पूछताछ में एसएमसी अधिकारियों को कई अहम जानकारियां मिली हैं। हर्षित जैन का मुख्य काम डब्बा ट्रेडिंग और सट्टेबाजी की रकम को हवाला से दुबई भेजना था. इसके बदले में उन्हें करोड़ों रुपये का कमीशन मिलता था.

माधुपुरा में गिरफ्तार क्रिकेट सट्टेबाजी और डब्बा ट्रेडिंग सट्टेबाजी घोटाले के मुख्य आरोपी हर्षित जैन के संबंध में एसएमसी अधिकारियों को कोई ठोस लिंक नहीं मिलने से पुलिस अधिकारी मामले से जुड़ी कई जानकारियों को लेकर असमंजस में थे। बहरहाल, उम्मीद है कि डब्बा ट्रेडिंग घोटाले के किंग दीपक ठक्कर के केस से जुड़े कई मामलों की कड़ियां गुजरात पुलिस के हाथ लग जाएंगी. दीपक ठक्कर से शुरुआती पूछताछ में पता चला कि हर्षित जैन गुजरात में अपने द्वारा चलाए जा रहे डब्बा ट्रेडिंग घोटाले से पैसे दुबई भेजने की चेन चला रहा था।

दुबई में रहते हुए, हर्षित जैन अमित मजीठिया का खास आदमी था, जिसने महादेव बुकी के साथ मिलकर देश में सबसे बड़ा क्रिकेट सट्टेबाजी घोटाला चलाया था। हर्षित जैन अपने सट्टेबाजी के सारे पैसे को हवाला के जरिए गुजरात से दुबई भेजने के लिए जिम्मेदार था। इस प्रकार, हर्षित जैन, दीपक ठक्कर और अमित मजीठिया पूरे घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर हर्षित जैन और अमित मजेठिया को भारत लाकर स्टेट मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से त्वरित पूछताछ के लिए स्थानीय एजेंसियों की मदद मांगी गई है। इसके अलावा दीपक ठक्कर की रिमांड पूरी होने के बाद अन्य एजेंसियां भी उससे पूछताछ करेंगी.

अहमदाबाद में डॉक्टरों की हड़ताल से बढ़ी परेशानी, कई गंभीर मरीज इलाज के लिए पहुंचे

अहमदाबाद, अहमदाबाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़तालः अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टरों की आज से शुरू हुई हड़ताल के बाद से कई सेवाएं बाधित हो गई हैं। हड़ताल के कारण कई गंभीर मरीज इलाज के लिए पहुंचे. अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल के कारण ओपीडी में भी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. सरकार की ओर से जारी सर्कुलर के खिलाफ स्टाइपेंड के मुद्दे पर सभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं.

डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज नाराज हो गये

मानसून के मौसम में कई तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, जिसके कारण अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ लग जाती है, ऐसे में जब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं, तो कई मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि दो दिन पहले सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 20 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था. हालांकि, इससे रेजिडेंट डॉक्टर नाराज हो गए और उन्होंने अपने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर फिर से हड़ताल पर जाने का फैसला किया। रेजिडेंट डॉक्टर आज से फिर हड़ताल पर चले गए हैं और इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद कर दी हैं।

हड़ताल का सबसे ज्यादा असर ओपीडी पर पड़ा

रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का अस्पताल की ओपीडी पर खासा असर पड़ा. हड़ताल के चलते सिविल अस्पताल परिसर में मरीज परेशान रहे। रेजिडेंट डॉक्टर सरकार द्वारा बढ़ाए गए 20 फीसदी स्टाइपेंड के मुकाबले 40 फीसदी स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं. हालांकि, उनके धरने और हड़ताल के कारण कई मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर बनने से पहले ली गई शपथ तोड़ दी और इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा।

अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं. गुजरात में रेजिडेंट डॉक्टरों को 1 लाख से ज्यादा का स्टाइपेंड दिया जाता था, जिसे 20 फीसदी बढ़ाकर 1.30 लाख कर दिया गया है. गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में इनका स्टाइपेंड 40 हजार से 70 हजार तक है.

पेरियार ललई सिंह यादव की 113 वी जयंती समारोह मनाया गया

कुशीनगर।ओम साई पब्लिक स्कूल रामकोला में पेरियार ललई सिंह यादव की 113 वीं जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम ललई सिंह यादव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए भगवन्त यादव ने कहा कि इनकी जीवन परिचय लम्बा संघर्ष से गुजरा है। पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार ई बी रामास्वामी नायकर के सच्चे शिष्य थे। वे आजीवन अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ संघर्ष करते रहे। उनके जीवन परिचय बताते हुए समाजसेवी भगवन्त यादव ने कहा कि एक समय ललई सिंह ने ग्वालियर पुलिस और आर्मी में हड़ताल करा दी, जिसके परिणामस्वरूप 29 मार्च 1947 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. मुकदमा चला, और उन्हें पांच साल के सश्रम कारावास की सजा हुई. 9 महीने जेल में रहे, और जब भारत आजाद हुआ, तब ग्वालियर स्टेट के भारत गणराज्य में विलय के बाद, वह 12 जनवरी 1948 को जेल से रिहा हुए.कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में प्रमुख रूप से राजेश यादव पूर्व सभासद,देवेंद्र यादव,पूर्व प्रधान भगवंत यादव, गृजेश यादव,रमेश यादव रहे।कार्यक्रम का अध्यक्षता रामसूरत शर्मा व संचालन पूर्व प्रधान विजय यादव ने की।पेरियार ललई सिंह यादव के जयंती कार्यक्रम में सुभाष गौतम, महातम यादव,संतोष यादव,सुरेंद्र यादव,शैलेश यादव,एडवोकेट पियूष यादव अन्तिम में सभा को ओमप्रकाश यादव संयोजक यादव महासभा ब्लाक अध्यक्ष व ओम साई पब्लिक स्कूल के प्रबंधक सीताराम यादव ने समापन कर सबके प्रति आभार प्रकट किया उपस्थित रहे।

ISRL के सीज़न 2 के पंजीकरण में 20% की वृद्धि

पुणे, 02 सितंबर, 2024: सीएट इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग (आईएसआरएल) फिर से शुरू हो रही है क्योंकि इसने सीजन 2 के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित राइडर नीलामी के लिए आधिकारिक तौर पर राइडर पंजीकरण बंद कर दिया है। अपने उद्घाटन सत्र की जबरदस्त सफलता के बाद लीग नई जमीन तैयार करने के लिए तैयार है, जिसमें दुनिया भर से प्रभावशाली 145 राइडर्स शामिल होंगे, जो विश्व स्तर पर सबसे रोमांचक मोटरस्पोर्ट्स आयोजनों में से एक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और भारत के एथलीटों के मैदान में शामिल होने से प्रतिक्रिया असाधारण से कम नहीं है। सीजन 1 की तुलना में भारतीय मूल के राइडर्स के पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि कैसे अधिक से अधिक घरेलू एथलीट आईएसआरएल को अपने कौशल दिखाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में देखते हैं। अनुभवी चैंपियनों और होनहार नई प्रतिभाओं के संयोजन वाले रोस्टर के साथ, सिएट घ्र्ींथ तेजी से खुद को सुपरक्रॉस रेसिंग की दुनिया में एक अग्रणी ताकत के रूप में स्थापित कर रहा है।

सिएट ISRL के सह-संस्थापक और निदेशक ईशान लोखंडे ने आगामी सीजन के लिए अपना उत्साह साझा करते हुए कहा, सीजन दो के लिए प्रतिक्रिया अभूतपूर्व रही है। हम भारतीय मोटरस्पोर्ट्स में एक नया युग देख रहे हैं, जहां सिएट घ्र्ींथ न केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, बल्कि भारत में सुपरक्रॉस के विकास के लिए एक उत्प्रेरक भी है। हमारा लक्ष्य खेल को और ऊपर उठाना है और एक ऐसा सीजन देना है जो बड़ा, साहसी और तेज हो, जो दुनिया भर के प्रशंसकों को लुभाए।

मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद के धंधुका के अनूठे शिवभक्त को सराहते हुए शुभकामना संदेश भेजा

\- 88 वर्ष की आयु में भी पेड़ों से सवा लाख बिल्व पत्र तोड़ कर भीमनाथ महादेव को भेजते हैं

गांधीनगर (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद जिले के धंधुका स्थित रंगपुर गाँव के 88 वर्षीय शिवभक्त एवं वृक्षप्रेमी हरजीभाई चौहाण को शुभकामना संदेश भेज कर उनकी सराहना की है।

मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटा रेल सम्पर्क प्रदान करने के लिए 309 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी

अहमदाबाद , स्वीकृत परियोजना व्यावसायिक केन्द्रों मुम्बई और इंदौर को सबसे छोटे रेल मार्ग से जोड़ने के अलावा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के उन जिलों को जोड़ेगी जो अब तक रेल मार्ग से नहीं जुड़े थे, इनमें महाराष्ट्र के 2 और मध्य प्रदेश के 4 जिले शामिल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने रेल मंत्रालय के तहत 18,036 करोड़ रुपये (लगभग) की कुल लागत वाली नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इंदौर और मनमाड के बीच प्रस्तावित नई लाइन सीधा सम्पर्क प्रदान करेगी और गतिशीलता में सुधार करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के लिए बेहतर दक्षता और सेवा विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी की नए भारत की कल्पना के अनुरूप है, जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से लोगों को ठआत्मनिर्भरठ बनाएगी, जिससे उनके लिए रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

यह परियोजना मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुआ है और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध सम्पर्क प्रदान करेगा।

यह परियोजना 2 राज्यों, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को कवर करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 309 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

इस परियोजना के साथ 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे आकांक्षी जिले बड़वानी को बेहतर सम्पर्क मिलेगा। नई रेलवे लाइन परियोजना से लगभग 1,000 गांवों और लगभग 30 लाख आबादी को सम्पर्क मिलेगा।

परियोजना देश के पश्चिमी/दक्षिण-पश्चिमी हिस्से को मध्य भारत से जोड़ने वाला छोटा रास्ता उपलब्ध कराकर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी। इससे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सहित उज्जैन-इंदौर क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन/धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।

परियोजना से पीथमपुर ऑटो क्लस्टर (90 बड़ी इकाइयां और 700 छोटे और मध्यम उद्योग) को जेएनपीए के गेटवे पोर्ट और अन्य राज्य बंदरगाहों से सीधा सम्पर्क मिलेगा। परियोजना मध्य प्रदेश के बाजरा उत्पादक जिलों और महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक जिलों को भी सीधा सम्पर्क प्रदान करेगी, जिससे देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में इसके वितरण में सुविधा होगी।

कृषि उत्पादों, उर्वरक, कंटेनर, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, पीओएल आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए यह एक आवश्यक मार्ग है। क्षमता वृद्धि कार्य के परिणामस्वरूप लगभग 26 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन है, जो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात (18 करोड़ लीटर) को कम करने और कार्बनडाइक्साइड उत्सर्जन (138 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद करेगा जो 5.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

स्कोडा ऑटो इंडिया ने ऑल-न्यू स्लाविया मोंटे कार्लो लॉन्च की

पहली5,000 बुकिंग्स पर उपभोक्ताओं को 30,000 रुपये के लाभ की घोषणा

स्कोडा ऑटो इंडियाने भारत में ऑल-न्यू स्लाविया मोर्टे कार्लोसंस्करण लॉन्च किया है। स्पोर्ट्स थीम को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी ने कुशाक और स्लाविया में ऑल-न्यू स्पोर्टलाइन रेंज भी लॉन्च की है।स्कोडा ऑटो ने इन कारों की खरीद के लिए जबर्दस्त ऑफर की घोषणा की। इस तरह कंपनी ने भारतीय उपभोक्ताओं को आकर्षक मूल्य पर अपनी पसंदीदा कार तलाश करने के विकल्पों को बढ़ाया है।

स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रैंड डायरेक्टर श्री पेट्र जनेबा ने इन नई पेशकश के बारे में कहा, ठमोंटे कार्लो बैज का ग्राहकों के साथ एक मजबूत संबंध है, जो खेल भावना और जीत के जज्बे की झलक देता है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम आज स्लाविया मोर्टे कॉर्लो को लॉन्च कर रहे हैं। यह भारत में स्कोडा ब्रैंड को आगे बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। भारत यूरोप के बाहर हमारे लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है।यह स्पेशल कार उन उपभोक्ताओं को बेहद पसंद आएगी, जो बेमिसाल, बारीक और स्पोर्टी स्टाइल की खूबसूरत कारों की तलाश में रहते हैं, जिससे उनका एक खास स्टाइल उभरकर आए। इस स्पेशल कार में हमने रैली मोंटे कार्लो में अपने 112 वर्ष, समृद्ध विरासत के 129 वर्षों और भारत में मौजूदगी के 24 वर्षों के अनुभवों को शामिल किया है।

एनिवर्सरी ऑफर

इस ऑल-न्यू रेंज को कंपनी की रैली मोंटे कार्लो में शामिल होने की 112 वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्चे किया गया है। स्कोडा ऑटो इंडियाने कुशाकऔर स्लावियाकी स्पोर्ट स्टाइल की मोंटे कार्लो और स्पोर्टलाइन रेंज की कार की खरीद पर उपभोक्ताओं को कई लाभ प्रदान कर रहा है।

अगस्त-2023 की तुलना में अगस्त-2024 में राज्य कर विभाग के राजस्व में 1,520 करोड़ की वृद्धि

अगस्त-2024 में राज्य के राजस्व विभाग को जीएसटी, वैट, बिजली शुल्क और व्यापार कर से रु.9,390 करोड़ प्राप्त हुए, जो अगस्त-2023 से 19% अधिक है।

अगस्त-2024 में राज्य को जीएसटी के तहत 5,714 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो अगस्त-2023 के राजस्व से 16% अधिक है।

अगस्त-2024 में राज्य को वैट के तहत रु.2,731 करोड़, बिजली शुल्क के तहत रु.926 करोड़ और व्यापार कर के तहत रु.21 करोड़ प्राप्त हुए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले पांच महीनों में जीएसटी, वैट, बिजली शुल्क और व्यापार कर से राज्य कर विभाग का राजस्व रु. 48,744 करोड़ था, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15% अधिक है।

जो करदाता जीएसटी पंजीकरण में नंबर प्राप्त करते समय बैंक खाते का विवरण प्रदान करने में विफल रहे हैं, वे तब तक अगला जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं कर देते। इस संबंध में जीएसटीएन द्वारा सिस्टम में डी.टी. 01 सितंबर 2024 से संशोधित।

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोनः 079-22921482 Mob.9375504122 , 9327086467 R.N.I. 63177/ 95